फरवरी 2024 ■ वर्ष : 33 ■ अंक : 6 ₹135

सिविल सर्विसेज़

क्रॉनिकल

1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

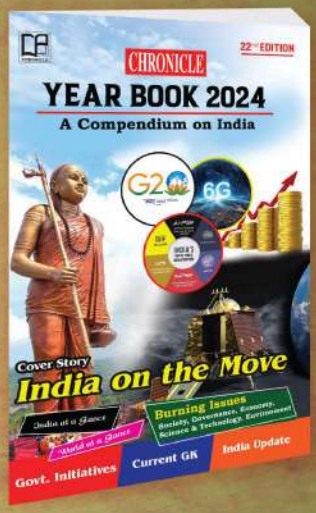

विशेषांक–5

सामान्य अध्ययन दृष्टिकोण

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु
46 अति महत्वपूर्ण विषयों की
परीक्षोपयोगी प्रस्तुति

अन्य आकर्षण

- न्यूज बुलेट्स
- चर्चित शब्दावली
- संसद प्रश्नोत्तरी
- समसामयिक प्रश्न
- PIB, AIR, PTI वनलाइनर
- पत्रिका सार : योजना, कुरुक्षेत्र एवं साइंस रिपोर्टर (दिसंबर 2023)
- परीक्षा सार : MPPSC - राज्य सेवा प्रा. परीक्षा 2023 तथा WBPSC - पश्चिम बंगाल सिविल सेवा (प्रा.) परीक्षा 2023 पर आधारित
- फैक्ट शीट : भारतीय खुदरा एवं ई-कॉमर्स उद्योग तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्र

विशेष आलेख

- भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली : नीतिगत अस्पष्टता को दूर करने के लिए सुधारोन्मुख प्रयास
- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना : समावेशी विकास में प्रगति हेतु व्यापक सुधार की आवश्यकता
- भारत में भौगोलिक संकेतक प्रणाली : प्रबंधन, लाभ एवं चुनौतियां
- भारत का ध्रुवीय अभियान : महत्व, चुनौतियां एवं पहलें
- कॉप-28 सम्मेलन : प्रमुख परिणाम एवं भविष्य की राह
- प्रेस एवं पत्र-पत्रिका पंजीकरण अधिनियम : विशेषताएं तथा महत्व

भारत सरकार के प्रमुख मंत्रालयों की उपलब्धियां

PIB द्वारा जारी मंत्रालयों की वर्षांत समीक्षा रिपोर्ट-2023 पर आधारित

फरवरी 2024
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल
1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

www.chronicleindia.in

सिविल सर्विसेज़
क्रॉनिकल
1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

facebook/civilserviceschronicle

फरवरी 2024
❑ वर्ष 33 ❑ अंक 6

इस अंक में

61 सामान्य अध्ययन दृष्टिकोण विशेषांक-5
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

सामयिक आलेख

06 भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली : नीतिगत अस्पष्टता को दूर करने के लिए सुधारोन्मुख प्रयास
10 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना : समावेशी विकास में प्रगति हेतु व्यापक सुधार की आवश्यकता
12 कॉप-28 सम्मेलन : प्रमुख परिणाम एवं भविष्य की राह

इन फोकस

15 प्रेस एवं पत्र-पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, 2023 : विशेषताएं तथा महत्व
16 भारत में भौगोलिक संकेतक प्रणाली : प्रबंधन, लाभ एवं चुनौतियां
18 भारत का ध्रुवीय अभियान : महत्व, चुनौतियां एवं पहलें

नियमित स्तंभ

राष्ट्रीय परिदृश्य 20-25
20 डाकघर अधिनियम, 2023
20 दूरसंचार अधिनियम-2023
21 मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023
22 जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन एवं केंद्र शासित प्रदेश (संशोधन) अधिनियम
22 अनुच्छेद 370 और 35ए का निरस्तीकरण बरकरार
23 विकसित भारत@2047
23 समर्थ क्यूरेटेड प्रशिक्षण कार्यक्रम
23 उल्फा के वार्ता समर्थक गुट के साथ त्रिपक्षीय समझौता
24 मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर (MA) गैर-कानूनी संगठन घोषित
24 आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की डेल्टा रैंकिंग
25 भारत में सड़क सुरक्षा

सामाजिक परिदृश्य 26-28
26 केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023
26 जनजातीय अभिविन्यास कार्यक्रम-आदि व्याख्यान

99 भारत सरकार के प्रमुख मंत्रालयों की उपलब्धियां

27 पीएम जनमन योजना पर सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियान
27 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पर बहु-हितधारक बैठक
28 कॉलेजों की मान्यता पर यूजीसी के मसौदा दिशा-निर्देश
28 लखपति दीदी सम्मेलन

विरासत एवं संस्कृति 29-32
29 महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती
30 डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि
30 गुजरात का गरबा : यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत
31 सांस्कृतिक विरासत संरक्षण हेतु यूनेस्को एशिया-प्रशांत पुरस्कार 2023
31 चन्नापटना खिलौने
32 काशी तमिल संगमम
32 हॉर्नबिल महोत्सव
32 स्वर्वेद महामंदिर

आर्थिक परिदृश्य 33-39
33 राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का पुनर्गठन
34 इन्फिनिटी फोरम 2.0 का आयोजन
34 इथेनॉल उत्पादन हेतु गन्ने के रस के दोहरे उपयोग की अनुमति
34 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट
35 27वां WAIPA विश्व निवेश सम्मेलन
35 भारत में लॉजिस्टिक्स लागत: आकलन एवं दीर्घकालिक रूपरेखा
36 पीएम गतिशक्ति के तहत 62वीं नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की बैठक
36 'ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया-2023' रिपोर्ट
37 मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक
37 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा NARCL को एनपीए का हस्तांतरण
37 लॉजिस्टिक्स ईज एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स-2023 रिपोर्ट
38 आसियान-भारत बाजरा महोत्सव

38 भारत एवं ADB के मध्य नीति-आधारित ऋण पत्र पर हस्ताक्षर
39 पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना में 2025 तक वृद्धि
39 वित्तीय आसूचना इकाई द्वारा 9 ऑफशोर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को नोटिस

अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं संगठन 40-46

40 भारत-भूटान सीमा पर एक मेगा सिटी परियोजना
40 लाल सागर में वाणिज्य की सुरक्षा हेतु ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन
41 भारत-रूस के मध्य सहयोग
41 इटली के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता साझेदारी समझौता
42 भारत-जर्मनी सैन्य सहयोग उप समूह की बैठक
43 भारत-कोरिया इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम
43 लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन का चरण-II (LeadIT 2.0)
44 विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्द्धात्मकता रैंकिंग
44 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग : सस्टेनेबिलिटी 2024
44 खाद्य सुरक्षा एवं पोषण का क्षेत्रीय अवलोकन-2023
45 अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद हेतु भारत का चुनाव
45 कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन में भारत का चुनाव
46 मानचित्र के माध्यम से : अर्जेंटीना
46 मानचित्र के माध्यम से : माउंट उलावुन
46 मानचित्र के माध्यम से : निकारागुआ

पर्यावरण एवं जैव विविधता 47-54

47 भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणीकरण योजना
48 अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की कोल 2023 रिपोर्ट
48 वैश्विक जलवायु 2011-2020 रिपोर्ट
49 एन्नोर तेल रिसाव
50 बहु-खतरा पूर्व चेतावनी प्रणाली की वैश्विक स्थिति 2023
50 भारत में तटीय कटाव
51 वैश्विक सूखा स्नैपशॉट रिपोर्ट
52 सीसीएसएस तकनीक के माध्यम से शुद्ध शून्य उत्सर्जन की लागत
53 प्लास्टिक प्रदूषण से मुकाबला
53 वायु प्रदूषण एवं मृत्यु दर
54 कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 55-60

55 3डी फोटोनिक क्रिस्टल प्राप्त करने का एक नवीन तरीका
55 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी सम्मेलन
56 मेफ्टाल और ड्रेस सिंड्रोम
57 सिकेल सेल रोग के लिए क्रिस्पर जीन थेरेपी
57 जामुन के पेड़ का प्रथम जीनोम अनुक्रमण
58 जापान का SLIM अंतरिक्ष यान
58 सूर्य की पहली पूर्ण-डिस्क छवियां कैप्चर
58 सर्वेक्षण जहाज संध्याक (यार्ड 3025)
59 आईएनएस कदमत्त का जापान के योकोसुका में प्रवेश
59 ऑफशोर गश्ती जहाजों की खरीद हेतु एमडीएल के साथ अनुबंध
60 नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपोजिटरी (NGDR) पोर्टल
60 जेनेरेटिव एआई पर ईवाई इंडिया रिपोर्ट

प्रतियोगिता क्रॉनिकल

न्यूज बुलेट्स 108-126
चर्चित शब्दावली 127
राज्य परिदृश्य 128-130
खेल परिदृश्य.....131-134
लघु संचिका 135-138
पत्रिका सार : योजना, कुरुक्षेत्र एवं साइंस रिपोर्टर 139-148
संसद प्रश्नोत्तरी 149-150
परीक्षा सार..... 151-157
फैक्ट शीट 158
समसामयिक प्रश्न 159-160
वन लाइनर..... 161-162

संपादक : एन.एन. ओझा
सहायक संपादक : सुजीत अवस्थी
अध्यक्ष : संजीव नन्दक्योलियार
उपाध्यक्ष : कीर्ति नंदिता
संपादकीय : 9582948817, cschindi@chronicleindia.in
विज्ञापन : 9953007627, advt@chronicleindia.in
सदस्यता : 9953007628/29, subscription@chronicleindia.in
प्रसार : 9953007630/31, circulation@chronicleindia.in
ऑनलाइन सेल : 9582219047, onlinesale@chronicleindia.in
व्यावसायिक कार्यालय : क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
ए-27 डी, सेक्टर-16, नोएडा-201301
Tel.: 0120-2514610-12, info@chronicleindia.in

क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.: प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार अपने हैं। उनसे संपादक का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है। संपादक की लिखित अनुमति के बिना इस पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सामग्री को उद्धृत या उसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका में छपे किसी भी विज्ञापन की सूचना की जांच स्वयं कर लें। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, विज्ञापनों में प्रकाशित दावों के लिए किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं है। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

क्रॉनिकल पब्लिकेशंस प्रा.लि. के लिए **प्रकाशक एवं मुद्रक-मृणाल ओझा** द्वारा एच-31, प्रथम तल ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नयी दिल्ली-110016, से प्रकाशित एवं इम्प्रेशन प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नंबर C-18-19-20-21, सेक्टर-59, नोएडा-201301 से मुद्रित- **संपादक एन.एन. ओझा**

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली

नीतिगत अस्पष्टता को दूर करने के लिए सुधारोन्मुख प्रयास

• डॉ. अमरजीत भार्गव

भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली अनुशासन बनाए रखने एवं सख्ती पर जोर देती है, जबकि इसके लिए समानुभूति से प्रेरित सुधारोन्मुखी उपायों की ओर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। देश की आपराधिक न्याय प्रणाली दिशाहीन है तथा नीतिगत अस्पष्टता की स्थिति में है। अतः यह अपेक्षा है कि सरकार द्वारा लाए गए नये कानून आपराधिक न्याय प्रणाली में नीतिगत अस्पष्टता को संबोधित करके दीर्घकाल से आवश्यक सकारात्मक परिवर्तनों को स्थापित करने में मदद करेंगे।

25 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद द्वारा पारित किए गए तीन नए आपराधिक न्याय विधेयकों को मंजूरी दे दी। इन तीन नए कानूनों में- भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023); भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023) शामिल हैं, जो औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे।

- इन तीनों कानूनों का पारित होना, भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। इन कानूनों का उद्देश्य विभिन्न अपराधों और दंडों की स्पष्ट परिभाषा का प्रावधान करके आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करना है। अवगत करा दें कि आपराधिक कानून और दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं।
- आपराधिक न्याय प्रणाली से तात्पर्य सरकार की उन एजेंसियों से है, जो कानून लागू करने, आपराधिक मामलों पर निर्णय देने तथा आपराधिक आचरण में सुधार करने के लिए कार्य करती हैं। सम्पूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत जेल प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा न्याय व्यवस्था तीनों को ही शामिल किया जाता है।
- वर्तमान भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की एक प्रणालीगत त्रुटि है कि यह दंड के किसी एक सिद्धांत का पालन नहीं करती, बल्कि यह अपनी सुविधा के आधार पर निवारण (deterrence), प्रतिशोध (retribution) एवं सुधार (reformation) के तीन सिद्धांतों के बीच झूलती रहती है। अतः उपर्युक्त संदर्भ में यह आवश्यक है कि निर्मित किए गए तीनों कानूनों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय आपराधिक न्यायिक प्रणाली पर दृष्टिपात किया जाए।

आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार हेतु नवीन अधिनियम

✓ भारतीय न्याय संहिता, 2023 : प्रमुख विशेषताएं

- भारतीय न्याय संहिता (BNS) ने भारतीय दंड संहिता (IPC) के उन प्रावधानों को बरकरार रखा है, जो हत्या, आत्महत्या के लिए उकसाने, हमले और गंभीर चोट पहुंचाने जैसे कृत्यों को अपराध मानते हैं। इसमें संगठित अपराध, आतंकवाद और कुछ आधारों पर किसी समूह द्वारा हत्या या गंभीर चोट जैसे नए अपराध जोड़े गए हैं।
- BNS में से राजद्रोह शब्द को हटा दिया गया है। इसके स्थान पर निम्नलिखित स्थितियों में दंड का प्रावधान किया गया है:
  - अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, या विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा देना या ऐसा करने का प्रयास करना,
  - अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करना, या
  - भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालना।
  - इन अपराधों में शब्दों या संकेतों का आदान-प्रदान, इलेक्ट्रॉनिक संचार या वित्तीय साधनों का उपयोग भी शामिल है।
- BNS की धारा 113 में गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 [Unlawful Activities (Prevention) Act-UAPA] की धारा 15 के तहत मौजूदा परिभाषा को अपनाने के लिए आतंकवाद के अपराध की परिभाषा को संशोधित किया गया है।
  - आतंकवाद के तहत ऐसी गतिविधियां शामिल हैं, जिनसे- देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरा हो, अथवा भारत के लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक उत्पन्न हो।
- BNS के तहत संगठित अपराध की श्रेणी में अपहरण, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, जमीन पर कब्जा, वित्तीय घोटाले और साइबर अपराध जैसे अपराधों को शामिल किया गया है।
- इसमें मॉब लिंचिंग अर्थात जाति, धर्म, लिंग, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर 5 या अधिक लोगों द्वारा की गई हत्या या गंभीर चोट को अपराध के रूप में शामिल किया गया है। ऐसी हत्या के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है।

✓ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 : प्रमुख विशेषताएं

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में CrPC के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखा गया है।
- CrPC के अनुसार, यदि किसी आरोपी ने कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिताया है, तो उसे व्यक्तिगत बॉण्ड (Personal Bond) पर रिहा किया जा सकता है। हालांकि यह मृत्युदंड वाले अपराधों पर लागू नहीं होता है। BNSS में उल्लेख किया गया है कि यह प्रावधान निम्नलिखित अपराधों के संदर्भ में भी लागू नहीं होगा:
  - आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध, और
  - ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध एक से अधिक अपराधों में कार्यवाही लंबित है।
- CrPC बलात्कार के मामलों सहित कुछ मामलों में आरोपी की मेडिकल जांच की अनुमति देता है। ऐसी जांच कम-से-कम एक सब इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा की जाती है। BNSS प्रावधान करता है कि कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसी जांच का अनुरोध कर सकता है।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना

समावेशी विकास में प्रगति हेतु व्यापक सुधार की आवश्यकता

• संपादकीय डेस्क

यह सभी विकसित और विकासशील देशों के हित में है कि वे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार करें, ताकि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में विश्वास बहाल किया जा सके और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में दिखाई देने वाले बिखराव और विखंडन को रोका जा सके।

हाल ही में आयोजित CoP28 सम्मेलन के दौरान 'वैश्विक स्टॉकटेक' (Global Stocktake) ने बहुपक्षीय वित्तीय संरचना में सुधार और वित्त के नए एवं अभिनव स्रोतों की पहचान करने में तेजी लाने के महत्व को रेखांकित किया।

* विकासशील देशों, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण (Global South) के समक्ष आने वाली वर्तमान विकासात्मक चुनौतियां और SDG's के लिए एजेंडा-2030 की दिशा में अपेक्षाकृत धीमी प्रगति वर्तमान वैश्विक वित्तीय संरचना की कमियों को उजागर करती है तथा व्यापक सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
* इस संदर्भ में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने अनेक बार वैश्विक वित्तीय संरचना को मौलिक रूप से प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 'यह सभी के लिए प्रभावी एवं निष्पक्ष लाभ प्रदान करे' तथा नवीन वित्तीय संरचना में 'लोगों, ग्रह एवं समृद्धि' को केंद्र में रखा जा सके।

वर्तमान वित्तीय संरचना से संबंधित चिंताएं

* मई 2023 में 'संयुक्त राष्ट्र सचिवालय' द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एवं कर संरचना में सुधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की सिफारिशों को रेखांकित करते हुए 'अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार' नामक शीर्षक से एक 'नीति पत्र' प्रकाशित किया गया।
* इसके अनुसार, वर्तमान अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना 1945 से कार्यरत है, जब इसे 'युद्धोत्तर काल के औद्योगिक देशों द्वारा खुद के आर्थिक हितों के लिए' डिजाइन किया गया था।
* यह वित्तीय संरचना वर्तमान वास्तविकताओं, आवश्यकताओं एवं चुनौतियों के साथ असंगत हो गई है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रणालीगत जोखिम, असमानता तथा भू-राजनीतिक परिवर्तन जैसी समस्याओं से निपटने में 'परंपरागत तथा अत्यधिक एकीकृत वित्तीय' संरचना अनुपयुक्त है।
* वर्तमान कुछ प्रमुख वित्तीय चिंताएं निम्नलिखित हैं-
  - विकासशील देशों को प्रदान किए जाने वाले ऋण की उच्च लागत कई देशों को उनके राजस्व के एक बड़े हिस्से को स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा में निवेश के स्थान पर ऋण सेवा भुगतान के लिए बाध्य करती है।
  - वैश्विक वित्तीय संकट के समय देशों की तरलता तक पहुंच (Access to Liquidity) में भारी भिन्नता देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए, अफ्रीकी देशों को अगस्त 2021 में आवंटित कुल एसडीआर का लगभग 33 बिलियन डॉलर या केवल 5% प्राप्त हुआ, जो कि एक प्रभावी COVID-19 प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए महाद्वीप की वित्तपोषण आवश्यकताओं से बहुत कम था।
  - अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामान्य वैश्विक समस्याओं-महामारी की तैयारी तथा जलवायु कार्रवाई आदि में बहुत कम निवेश किया गया है। इसी प्रकार, अन्य चुनौतियों में अस्थिर वित्तीय बाजार एवं पूंजी प्रवाह, आवर्ती वैश्विक वित्तीय संकट तथा संप्रभु ऋण संकट शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की आवश्यकता क्यों?

* **अपर्याप्त फंडिंग:** सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने की वैश्विक प्रतिबद्धताओं और प्रतिज्ञाओं के बावजूद, फंडिंग की वास्तविक मात्रा लक्ष्य से कम है। इसमें पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDG) जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों में की गई प्रतिबद्धताएं शामिल हैं।
* **पूर्वानुमान की कमी:** सतत विकास पहलों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक वित्त की उपलब्धता अक्सर अपेक्षित मात्रा से कम होती है, जिससे देशों और संगठनों के लिए दीर्घकालिक परियोजनाओं की योजना बनाना और उन्हें लागू करना मुश्किल हो जाता है। वित्त की यह अप्रत्याशितता (Unpredictability) गंभीर वैश्विक चुनौतियों से निपटने में प्रगति को बाधित करती है।
* **क्षेत्रीय असमानताएं:** विभिन्न क्षेत्रों के मध्य वित्त संबंधी असमानताएं मौजूद हैं। वित्त का एक महत्वपूर्ण हिस्सा धनी देशों या विशिष्ट क्षेत्रों के पास संकेंद्रित है। जबकि निम्न और मध्यम आय वाले देशों, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण (Global South) को पर्याप्त वित्तीय संसाधनों तक पहुंच स्थापित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
* **शर्तें और प्रतिबंध:** अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से मिलने वाला वित्त अक्सर व्यापक शर्तों और प्रतिबंधों के साथ प्रेषित किया जाता है। इस प्रकार के प्रतिबंध प्राप्तकर्ता देशों के लचीलेपन और संप्रभुता (Resilience and Sovereignty) को सीमित करते हैं। ये स्थितियां सतत विकास पहल को बढ़ावा देने के लिए वित्त के प्रभावी उपयोग में बाधा उत्पन्न करती हैं।
* **अपर्याप्त कार्यान्वयन:** वित्त उपलब्ध होने पर भी इसके वास्तविक संवितरण और कार्यान्वयन में देरी नीतियों को अप्रभावी बनती है। प्रशासनिक अड़चनें, नौकरशाही प्रक्रियाएं और अक्षम तंत्र देरी में योगदान करते हैं तथा परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हैं।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार हेतु संभावित कदम

* **वैश्विक आर्थिक प्रशासन में सुधार एवं मजबूती:** वैश्विक आर्थिक प्रशासन में सुधार और मजबूती के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (IFIs) के प्रशासन की पद्धति में परिवर्तन करने तथा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की सुसंगतता को व्यवस्थित करने के लिए एक 'प्रतिनिधि शीर्ष निकाय' की स्थापना की जानी चाहिए।
* **ऋण राहत प्रदान करना तथा संप्रभु ऋण की लागत में कमी करना:** ऋण राहत देने और संप्रभु ऋण की लागत में कमी करने

कॉप–28 सम्मेलन

प्रमुख परिणाम एवं भविष्य की राह

• महेंद्र चिलकोटी

रियो शिखर सम्मेलन एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के आरंभ के बाद से विगत तीन दशकों में UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन (CoP) ने महत्वाकांक्षा और जिम्मेदारियों को निर्धारित करने, उनकी पहचान करने तथा जलवायु उपायों का आकलन करने के लिए प्रत्येक वर्ष सदस्य देशों को आमंत्रित किया है। सम्मेलन के 21वें सत्र में पेरिस समझौता हुआ, जिसने वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5°C तक सीमित करने और जलवायु परिवर्तन के पहले से मौजूद प्रभावों के अनुकूल कार्य करने हेतु वैश्विक सामूहिक कार्रवाई के लिए सहमति व्यक्ति की।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, 2023 या यूएनएफसीसीसी (UNFCCC) के पक्षकारों के सम्मेलन की 28वीं बैठक [COP-28] 30 नवंबर से 13 दिसंबर, 2023 के मध्य संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में आयोजित की गई।

* 1992 में पहले संयुक्त राष्ट्र जलवायु समझौते के बाद से पक्षकारों का सम्मेलन (Conference of Parties) प्रत्येक वर्ष (कोविड-19 महामारी के कारण 2020 को छोड़कर) आयोजित किया जाता रहा है।
  - इस आयोजन का उद्देश्य सरकारों को वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रभावों के अनुकूल नीतियों पर सहमत करना है।

वैश्विक स्टॉकटेक रिपोर्ट

* वैश्विक स्टॉकटेक (Global Stocktake) देशों और हितधारकों के लिए यह देखने की एक प्रक्रिया है कि वे पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में कहां प्रगति कर रहे हैं; और कहां नहीं। इसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस (GHGs) उत्सर्जन को कम करने तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में संक्रमण के लिए अलग-अलग देशों के प्रयासों का आकलन करना है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

* पेरिस समझौते ने देशों को लक्ष्य निर्धारित करने और जलवायु संकट की तात्कालिकता का संकेत देने के लिए प्रेरित किया है।
* सरकारों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को जीवाश्म ईंधन व्यवसायों से दूर करने के तरीकों का समर्थन करने की आवश्यकता है तथा देशों और समुदायों को प्रयासों को मजबूत करना चाहिए।
* 2030 तक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 43% तक कम करने और 2035 में 60% तक कम करने तथा वैश्विक स्तर पर 2050 तक शुद्ध शून्य CO_2 उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक महत्वाकांक्षा की आवश्यकता है।
* अनुकूलन (Adaptation) पर पारदर्शी रिपोर्टिंग, समझ, कार्यान्वयन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक कर सकती है और उसे बढ़ा सकती है।
* तत्काल और बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रवाह को जलवायु-लचीले विकास के अनुरूप करने की आवश्यकता है।
* निम्न ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु-लचीले विकास का समर्थन करने के लिए वित्तीय प्रवाह में पर्याप्त बदलाव आवश्यक है।
* वनों की कटाई और भूमि-क्षरण को रोकना होगा तथा उत्सर्जन को कम करने और कार्बन सिंक को संरक्षित करने और बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना होगा।

कॉप–28 : चर्चा के विषय एवं अन्य बिंदु

* **जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना:** यह इस सम्मेलन की एक बड़ी सफलता थी; लगभग 200 देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ने और जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता को स्वीकार किया। यह वैश्विक तापन को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के पेरिस समझौते के लक्ष्य के अनुरूप है।
* **सहयोग को प्रोत्साहित करना:** COP-28 ने जलवायु संकट से निपटने के लिए सरकारों, व्यवसायों और नागरिक समाज के बीच सहयोग के महत्व पर जोर दिया। सम्मेलन में साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहल की गईं, जैसे 'क्लाइमेट एक्शन एक्सेलेरेटर' प्लेटफॉर्म का आरंभ आदि।
* **समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना:** राजनीतिक वार्ताओं के अलावा, COP-28 ने जलवायु संकट के लिए कई नवीन समाधानों का भी प्रदर्शन किया।
* **जलवायु वित्त में वृद्धि:** सम्मेलन में 2024 में जलवायु वित्त के लिए एक नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित करने पर भी चर्चा हुई। इसका उद्देश्य मौजूदा 100 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष के लक्ष्य को आगे बढ़ाना तथा विकासशील देशों को उनकी जलवायु कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना है।
* **उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य:** बैठक में देश, पेरिस सम्मेलन (2015) में निर्धारित वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप, महत्वाकांक्षी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारित करने के लिए वार्ता में शामिल हुए।
* **हानि एवं क्षति पर ध्यान केंद्रित करना:** COP-28 में सुभेद्य देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, जैसे समुद्र के बढ़ते स्तर और चरम मौसम की घटनाओं से निपटने में मदद करने के लिए एक नए कोष की स्थापना की गई। यह एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि विकासशील देश लंबे समय से उन नुकसानों और क्षति से निपटने के लिए वित्तीय सहायता की मांग करते रहे हैं, जिनका सामना वे पहले से कर रहे हैं।
* **निजी क्षेत्र के निवेश की भूमिका:** जलवायु कार्यों में निजी क्षेत्र के निवेश की भूमिका पर मंथन किया गया, जिसमें इस बात पर चर्चा हुई कि जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए निजी पूंजी को प्रभावी ढंग से कैसे जुटाया जा सकता है।

in फोकस

- प्रेस एवं पत्र–पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, 2023: विशेषताएं तथा महत्व
- भारत में भौगोलिक संकेतक प्रणाली : प्रबंधन, लाभ एवं चुनौतियां
- भारत का ध्रुवीय अभियान : महत्व, चुनौतियां एवं पहलें

प्रेस एवं पत्र–पत्रिका पंजीकरण अधिनियम,2023

विशेषताएं तथा महत्व

28 दिसंबर, 2023 को प्रेस एवं पत्र-पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, 2023 (The Press and Registration of Periodicals Act, 2023) को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गई। लोक सभा द्वारा इसे 21 दिसंबर, 2023 को तथा राज्य सभा द्वारा इसे 3 अगस्त, 2023 को पारित किया गया था।

- इस अधिनियम का उद्देश्य औपनिवेशिक युग के 'प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867' [Press and Registration of Books (PRB) Act 1867] को प्रतिस्थापित करना है। इस प्रकार, एक अन्य ब्रिटिशकालीन कानूनी विरासत को समाप्त करते हुए प्रेस एवं पत्र-पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास किया गया है।
- वर्तमान परिप्रेक्ष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्मित किए गए इस नवीन कानून की विशेषताओं एवं महत्व से परिचित होने के लिए एक व्यापक विश्लेषण की आवश्यकता है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- **शीर्षक आवंटन और पंजीकरण प्रमाण-पत्र के अनुदान पर भौतिक इंटरफेस की आवश्यकता नहीं:** यह अधिनियम प्रेस रजिस्ट्रार जनरल (PRG) द्वारा शीर्षक सत्यापन और पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन करने हेतु एक सरल ऑनलाइन तंत्र प्रदान करता है।
  - **महत्त्व:** यह PRG को प्रक्रिया को तेजी से ट्रैक करने में सक्षम बनाएगा।
- **स्थानीय प्राधिकारियों/जिला मजिस्ट्रेट (DM) की सीमित भूमिका:** प्रकाशकों और प्रिंटिंग प्रेसों को स्थानीय प्राधिकारी के समक्ष कोई घोषणा या उसका प्रमाणीकरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
  - **ऑनलाइन सूचना की आवश्यकता:** प्रिंटिंग प्रेसों को केवल प्रेस रजिस्ट्रार जनरल (PRG) और स्थानीय प्राधिकारी को ऑनलाइन सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
  - **आवेदन प्राप्त होने पर समय सीमा:** जिला मजिस्ट्रेट (DM) से 60 दिनों के भीतर प्रेस रजिस्ट्रार जनरल (PRG) को अपनी टिप्पणियां/एनओसी (Comments/NOC) प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। इसके बाद PRG पंजीकरण देने का निर्णय लेगा।
- **पत्रिकाओं पर प्रतिबंध:** जिस व्यक्ति को किसी अदालत द्वारा आतंकवादी कृत्य या गैर-कानूनी गतिविधियों से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, या राज्य की सुरक्षा के खिलाफ कुछ भी किया गया हो, उसे पत्रिका निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- **किसी विदेशी पत्रिका की प्रतिकृति/पुनर्मुद्रण संस्करण के संदर्भ में प्रावधान:** इसकी छपाई के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी और प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के साथ इसके पंजीकरण की आवश्यकता होगी।
- **एक विश्वसनीय अपीलीय बोर्ड:** अधिनियम में एक विश्वसनीय अपीलीय तंत्र का प्रावधान किया गया है, जिसकी अध्यक्षता भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष करेंगे।

नवीन अधिनियम तथा प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम–1867 में अंतर

- **ऑनलाइन सुविधा के स्तर पर:** अब प्रिंटिंग प्रेसों को प्रेस रजिस्ट्रार जनरल (PRG) और डीएम के समक्ष केवल एक ऑनलाइन सूचना दाखिल करनी होगी, जबकि पहले डीएम के समक्ष घोषणा (Declaration) दाखिल करनी होती थी।
- **सजा:** PRB Act, 1867 में कानून के उल्लंघन की स्थिति में गंभीर दंड और 6 महीने तक की कैद का प्रावधान किया गया था। हालांकि, वर्ष 2023 का अधिनियम केवल चरम मामलों (Extreme Cases) में ही 6 महीने तक की जेल की सजा का प्रावधान करता है।
  - **उदाहरण के लिए-** यदि कोई पत्रिका पंजीकरण प्रमाण-पत्र (Registration Certificate) के बिना प्रकाशित की जाती है और प्रकाशक PRG द्वारा इस आशय का निर्देश जारी किए जाने के 6 महीने बाद भी ऐसे प्रकाशन की छपाई जारी रखता है, तो उसे सजा हो सकती है।
  - कुछ उल्लंघनों के लिए पहले की तरह दोषसिद्धि के स्थान पर वित्तीय दंड का प्रावधान किया गया है।

राजव्यवस्था

- डाकघर अधिनियम, 2023
- दूरसंचार अधिनियम-2023
- मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023
- जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन एवं केंद्र शासित प्रदेश (संशोधन) अधिनियम

न्यायपालिका

- अनुच्छेद 370 और 35ए का निरस्तीकरण बरकरार

कार्यक्रम एवं पहल

- विकसित भारत@2047
- समर्थ क्यूरेटेड प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय सुरक्षा

- उल्फा के वार्ता समर्थक गुट के साथ त्रिपक्षीय समझौता
- मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर (MA) गैर-कानूनी संगठन घोषित

रिपोर्ट एवं सूचकांक

- आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की डेल्टा रैंकिंग

राजव्यवस्था

डाकघर अधिनियम, 2023

24 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति द्वारा 'डाकघर अधिनियम, 2023' (Post Office Act, 2023) को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इसे विधेयक के रूप में राज्य सभा द्वारा 4 दिसंबर, 2023 को तथा लोक सभा द्वारा 18 दिसंबर, 2023 को पारित किया गया।

- यह अधिनियम **125 वर्ष** पुराने **भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898** का स्थान लिया है।
- अधिनियम का उद्देश्य **'भारत में डाकघर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना'** है।

अधिनियम में मुख्य प्रावधान

- यह अधिनियम केंद्र सरकार के एक विभागीय उपक्रम, इंडिया पोस्ट को नियंत्रित करता है।
- नए अधिनियम के अनुसार सरकार को पत्र संप्रेषित करने का विशेषाधिकार नहीं होगा। भारतीय डाक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं नियमों के अंतर्गत निर्धारित की जाएंगी।
- केंद्र सरकार को कुछ निर्दिष्ट आधारों पर इंडिया पोस्ट के माध्यम से प्रसारित किसी लेख को रोकने का अधिकार होगा। ये आधार निम्नलिखित हैं-
  (i) राज्य की सुरक्षा,
  (ii) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध,
  (iii) सार्वजनिक व्यवस्था,
  (iv) आपातकाल,
  (v) सार्वजनिक सुरक्षा या
  (vi) किसी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर।
- अधिनियम में पहली बार निजी कूरियर सेवाओं को अपने दायरे में लाकर उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है।
- यह डाक सेवाओं के महानिदेशक की शक्तियों को डाक संचालन से परे विस्तारित करता है, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अतिरिक्त सेवाओं से संबंधित गतिविधियों की देखरेख करने और संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता के बिना शुल्क स्थापित करने का अधिकार देता है।
- यह अधिनियम केंद्र सरकार की अधिसूचना के माध्यम से उपर्युक्त आधारों पर वस्तुओं के अवरोधन, उन्हें खोलने या हिरासत में लेने के लिए अधिकारियों को सशक्त बनाने का या अन्य कानूनों का अनुपालन का अधिकार देता है।
- यह डाक अधिकारियों को उन मामलों में डाक वस्तुओं को सीमा शुल्क अधिकारियों को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, जहां उन्हें ऐसी वस्तुएं होने का संदेह है, जो निषिद्ध हों या शुल्क के अधीन हों।

दूरसंचार अधिनियम-2023

24 दिसंबर, 2023 को दूरसंचार अधिनियम, 2023 (Telecommunications Act, 2023) को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गई। विधेयक के रूप में इसे 20 दिसंबर, 2023 को लोक सभा द्वारा तथा 21 दिसंबर, 2023 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया।

- **नवीन अधिनियम का उद्देश्य** प्राधिकरण प्रणाली (Authorization System) में परिवर्तन करके दूरसंचार नेटवर्क के लिए मौजूदा लाइसेंसिंग प्रणाली (Licensing System) को सुव्यवस्थित करना है।
- वर्तमान में, दूरसंचार विभाग 100 से अधिक प्रकार के **लाइसेंस, पंजीकरण और अनुमतियां** जारी करता है। अधिनियम का लक्ष्य उनमें से कई को एक ही प्राधिकरण प्रक्रिया में समेकित करना है।
- दूरसंचार अधिनियम, 2023 **भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम, 1950 को प्रतिस्थापित** करता है।

सामाजिक परिदृश्य

विधेयक एवं अधिनियम

- केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023

अति संवेदनशील वर्ग

- जनजातीय अभिविन्यास कार्यक्रम-आदि व्याख्यान
- पीएम जनमन योजना पर सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियान

बैठक एवं सम्मेलन

- लखपति दीदी सम्मेलन

सामाजिक सुरक्षा

- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पर बहु-हितधारक बैठक
- कॉलेजों की मान्यता पर यूजीसी के मसौदा दिशा-निर्देश

विधेयक एवं अधिनियम

केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023

केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2023 (Central Universities (Amendment) Bill, 2023) को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त हो गई।

- इसे 13 दिसंबर, 2023 को राज्य सभा द्वारा तथा 7 दिसंबर, 2023 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया।
- यह विधेयक तेलंगाना राज्य के मुलुगु में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (Sammakka Sarakka Central Tribal University) की स्थापना का प्रावधान करता है।
- इस विधेयक के माध्यम से **'केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन** किया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 को संपूर्ण भारत के विभिन्न राज्यों में **शिक्षण एवं अनुसंधान गतिविधियों के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा समावेशन हेतु अधिनियमित** किया गया था।
- विधेयक का **प्राथमिक उद्देश्य** विशेष रूप से भारत की **जनजातीय आबादी को उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान सुविधाओं के अवसर प्रदान करना** है। यह विधेयक हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए शैक्षिक अवसरों और परिणामों में सुधार के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है।
- ज्ञातव्य है कि **आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014** में प्रावधान किया गया था कि केंद्र सरकार तेलंगाना राज्य में एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी।
- प्रस्तावित विश्वविद्यालय में **11 विभागों वाले पांच स्कूलों के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट स्तर के पाठ्यक्रम** आरंभ किए जाएंगे।
- इस जनजातीय विश्वविद्यालय के संचालन के **शुरुआती 7 वर्षों के लिए कुल 2790 अंडर-ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट छात्रों का नामांकन प्रस्तावित** है।
- यह विश्वविद्यालय **889.07 करोड़ रुपये की लागत** से स्थापित किया जाएगा।
- इस विश्वविद्यालय की स्थापना से **संकाय और गैर-संकाय पदों के रूप में प्रत्यक्ष रोजगार** के अवसर उत्पन्न होंगे।
- इसके परिणामस्वरूप कई **सेवाओं और वाणिज्यिक गतिविधियों** के माध्यम से आस-पास के क्षेत्रों का विकास होगा, जिसके परिणामस्वरूप अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- विश्वविद्यालय का नाम सम्मक्का और सरलाम्मा (सरक्का) नामक मां और बेटी के नाम पर रखा गया है, इन्हें तेलंगाना में आदिवासी समुदायों की रक्षा के लिए भेजी गई आदिपराशक्ति का प्रतीक माना जाता है।

अति संवेदनशील वर्ग

जनजातीय अभिविन्यास कार्यक्रम-आदि व्याख्यान

21 दिसंबर, 2023 को नई दिल्ली में केंद्रीय जनजातीय कार्य और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने दो दिवसीय 'जनजातीय अभिविन्यास कार्यक्रम-आदि व्याख्यान' (Tribal Orientation Programme-Adi Vyakhyan) का उद्घाटन किया।

- उद्घाटन कार्यक्रम में **5 राज्यों- छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम** के मुंडा समुदायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

विरासत एवं संस्कृति

व्यक्तित्व
- महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती
- डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि

सांस्कृतिक विरासत
- गुजरात का गरबा : यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत
- सांस्कृतिक विरासत संरक्षण हेतु यूनेस्को एशिया-प्रशांत पुरस्कार 2023

कला के विविध रुप
- चन्नापटना खिलौने

उत्सव एवं पर्व
- काशी तमिल संगमम
- हॉर्नबिल महोत्सव

मंदिर एवं स्मारक
- स्वर्वेद महामंदिर

व्यक्तित्व

महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती

25 दिसंबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जाने-माने विद्वान, शिक्षा सुधारक और राजनीतिज्ञ पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 'पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं' के 11 खंडों की प्रथम श्रृंखला का विमोचन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया।

जीवन परिचय

- **संक्षिप्त परिचय:** पं. मदन मोहन मालवीय एक महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद तथा एक बड़े समाज सुधारक थे।
- **जन्म एवं शिक्षा:** पं. मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर, 1861 को इलाहाबाद (वर्तमान में प्रयागराज) में हुआ था और उन्होंने 'पाठशाला' प्रणाली के तहत प्रारंभिक शिक्षा ली थी तथा वे संस्कृत में पारंगत थे।
- **उपाधियां:** महात्मा गांधी द्वारा उन्हें 'महामना' की उपाधि दी गई, जबकि भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. एस. राधाकृष्णन ने मालवीय को 'कर्मयोगी' का दर्जा दिया था।
- **पुरस्कार एवं सम्मान:** वर्ष 2015 में पंडित मदनमोहन मालवीय को मरणोपरांत देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से नवाजा गया।

सामाजिक योगदान

- **जातिगत विभेद का विरोध:** इतिहासकार वी. सी. साहू के अनुसार हिन्दू राष्ट्रवाद के समर्थक मदन मोहन मालवीय देश से जातिगत बेड़ियों को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने दलितों के मन्दिरों में प्रवेश निषेध की बुराई के खिलाफ देश भर में आंदोलन चलाया।
- **मजदूर कल्याण:** मालवीय जी ने 'गिरमिटिया मजदूरी' प्रथा को समाप्त करने में अहम् भूमिका निभाई।
- 'गिरमिटिया मजदूरों' को चीनी, कपास तथा चाय बागानों आदि में कार्य करने के लिये वेस्टइंडीज, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया में ब्रिटिश कालोनियों में भेजा जाता था।
- **संगठन की स्थापना:** मालवीय ने 1905 में गंगा पर बांध बनाए जाने के विरोध में गंगा महासभा (Ganga Mahasabha) की स्थापना की।
  - उन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना में मदद की, जो विविध स्थानीय हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलनों को एक साथ लाया।

शैक्षिक योगदान

- पं. मदन मोहन मालवीय एक विद्वान और विचारक थे, जिन्होंने नागरिकों के बीच शिक्षा के प्रसार की दिशा में काफी काम किया।
- **विश्वविद्यालय की स्थापना:** मालवीय ने भारतीयों के बीच आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया तथा 1916 में वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) की सह-स्थापना की।
  - मालवीय 1919 से 1938 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे।
- **पुस्तकालय की स्थापना:** उन्होंने 15 दिसंबर, 1889 को अपने मित्र लाला ब्रजमोहन भल्ला के साथ इलाहाबाद में 'भारती भवन पुस्तकालय' (Bharati Bhawan Library) की स्थापना की।

राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान

- एक राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मदन मोहन के जीवन की शुरुआत वर्ष 1886 में कलकत्ता में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में भाग लेने के साथ हुई।
- मालवीय 1909,1918 और 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्होंने 1916 के लखनऊ समझौते के तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडलों का विरोध किया।

उद्योग एवं व्यवसाय

- राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का पुनर्गठन
- इन्फिनिटी फोरम 2.0 का आयोजन
- इथेनॉल उत्पादन हेतु गन्ने के रस के दोहरे उपयोग की अनुमति
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट

बैठक एवं सम्मेलन

- 27वां WAIPA विश्व निवेश सम्मेलन

अवसंरचना

- भारत में लॉजिस्टिक्स लागत: आकलन एवं दीर्घकालिक रूपरेखा
- पीएम गतिशक्ति के तहत 62वीं नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की बैठक

मुद्रा एवं बैंकिंग

- 'ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया-2023' रिपोर्ट
- मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा NARCL को एनपीए का हस्तांतरण

रिपोर्ट एवं सूचकांक

- लॉजिस्टिक्स ईज एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स-2023 रिपोर्ट

कृषि एवं संबंधित क्षेत्र

- आसियान-भारत बाजरा महोत्सव

व्यापार एवं निवेश

- भारत एवं ADB के मध्य नीति-आधारित ऋण पत्र पर हस्ताक्षर

योजना एवं कार्यक्रम

- पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना में 2025 तक वृद्धि

वित्त क्षेत्र

- वित्तीय आसूचना इकाई द्वारा 9 ऑफशोर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को नोटिस

उद्योग एवं व्यवसाय

राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का पुनर्गठन

18 दिसंबर, 2023 को केंद्र सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद' (National Startup Advisory Council: NSAC) का पुनर्गठन किया गया तथा 31 गैर-आधिकारिक सदस्यों (Non-Official Members) को नामित किया गया।

- ये सदस्य, स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र में **अलग-अलग हितधारकों का प्रतिनिधित्व** करते हैं। इनमें सफल **स्टार्टअप के संस्थापक, स्केलिंग कंपनियों में अनुभव रखने वाले व्यक्ति** तथा स्टार्टअप निवेशकों के हितों से जुड़े लोग शामिल हैं।
  - नामांकित उल्लेखनीय व्यक्तियों में **अर्बन कंपनी से अभिराज सिंह भाल और स्नैपडील से कुणाल बहल** शामिल हैं।
- गैर-आधिकारिक सदस्यों का **कार्यकाल सामान्यत: 2 वर्ष** का होता है। परिषद का पुनर्गठन प्रारंभिक कार्यकाल के पूरा होने के बाद होता है।
- **उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग** (DPIIT) ने देश में नवाचार और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण हेतु आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए **जनवरी 2020 में परिषद का गठन** किया था।
- यह परिषद, भारत में सतत **आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के व्यापक अवसर उत्पन्न करने** के सरकार के लक्ष्य को हासिल करने में सलाहकार की भूमिका निभाती है।
- परिषद **विशेषकर नागरिकों और छात्रों** के बीच नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के उपाय सुझाती है।
  - इसका **उद्देश्य अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों** सहित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना भी है।
- NSAC की **अध्यक्षता, भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री** द्वारा की जाती है। **इसकी 8वीं बैठक 19 दिसंबर** को आयोजित की गई।
  - इसके **पदेन सदस्यों** में संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के नामांकित व्यक्ति शामिल होते हैं, जो संयुक्त सचिव पद से नीचे के नहीं होते।
- **भारतीय उद्योग परिसंघ** (CII) जैसे उद्योग मंडलों के अध्यक्ष भी NSAC का हिस्सा हैं, जो समग्र परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं।
- NSAC का पुनर्गठन भारत में **नवाचार को बढ़ावा देने और स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता** को दर्शाता है। हितधारकों का विविध प्रतिनिधित्व चुनौतियों का समाधान करने और स्टार्टअप क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने हेतु व्यापक दृष्टिकोण बनाने में योगदान देता है।
- **स्टार्ट-अप इंडिया पहल को वर्ष 2016** में लॉन्च किया गया था। यह भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जो स्टार्टअप संस्कृति को उत्प्रेरित करती है और देश में नवाचार और उद्यमिता के लिए एक मजबूत, समावेशी पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करती है।
  - स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत विभिन्न **नीतिगत उपायों, प्रोत्साहनों और पहलों** के माध्यम से स्टार्टअप्स को समर्थन एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इस पहल का उद्देश्य स्टार्टअप को बढ़ावा देकर, बड़े पैमाने पर सतत आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में योगदान करना है।
- **स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम** (SISFS) स्टार्टअप्स को उनके **शुरुआती चरण में वित्तीय सहायता** प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है।
  - SISFS का **प्राथमिक लक्ष्य स्टार्टअप्स को शुरुआती फंडिंग प्रदान करके उनका समर्थन करना** है, ताकि उन्हें अपने परिचालन को शुरू करने और उनके विकास में योगदान देने में मदद मिल सके।

अंतरराष्ट्रीय संबंध व संगठन

भारत के पड़ोसी देश
- भारत-भूटान सीमा पर एक मेगा सिटी परियोजना

अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम
- लाल सागर में वाणिज्य की सुरक्षा हेतु ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन

द्विपक्षीय संबंध
- भारत-रूस के मध्य सहयोग
- इटली के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता साझेदारी समझौता
- भारत-जर्मनी सैन्य सहयोग उप समूह की बैठक
- भारत-कोरिया इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम

वैश्विक पहल
- लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन का चरण-II (LeadIT 2.0)

सूचकांक एवं रिपोर्ट
- विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग
- क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग: सस्टेनेबिलिटी 2024
- खाद्य सुरक्षा एवं पोषण का क्षेत्रीय अवलोकन-2023

संगठन एवं फोरम
- अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद हेतु भारत का चुनाव
- कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन में भारत का चुनाव

मानचित्र के माध्यम से
- अर्जेंटीना
- निकारागुआ
- माउंट उलावुन में ज्वालामुखी विस्फोट

भारत के पड़ोसी देश

भारत-भूटान सीमा पर एक मेगा सिटी परियोजना

17 दिसंबर, 2023 को भूटान के राजा 'जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक' ने भारतीय सीमा के पास 1,000 वर्ग किमी. क्षेत्र में विस्तृत एक मेगा सिटी परियोजना- **'गेलेफू विशेष प्रशासन क्षेत्र'** (Gelephu Special Administration Region) की योजना का अनावरण किया।

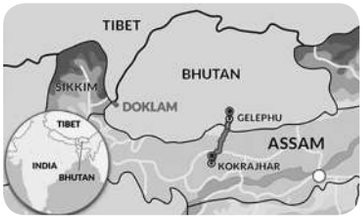

- यह परियोजना **क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा** देने के लिए भूटान को असम के साथ आर्थिक रूप से जोड़ेगी।
- इस **परियोजना का उद्देश्य** भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर असम के माध्यम से दक्षिण एशिया को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने वाला एक आर्थिक मार्ग स्थापित करना है।
- यह परियोजना **संपूर्ण जिले के विशेष आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा** होगी। गेलेफू भारत और भूटान के बीच तीन प्रवेश बिंदुओं में से एक है, अन्य स्थान- इसके पूर्व में समद्रुप जोंगखर और पश्चिम में फुंटशोलिंग हैं।
- **गेलेफू विशेष प्रशासनिक क्षेत्र** (SAR) विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अलग-अलग कानून लागू करेगा और एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की योजना को शामिल करेगा।
- इसमें गेलेफू तक **भारत-भूटान रेलवे लाइन का विकास** शामिल है, जिसका लक्ष्य भूटान को म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और सिंगापुर से जोड़ना है। यह परियोजना भूटान के नीतिगत स्तर पर **'अंदर की ओर देखने वाले देश'** (Inward looking country) से **'बाहर की ओर देखने'** (Outward looking country) वाले देश में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है।
- यह परियोजना **'सकल राष्ट्रीय खुशहाली'** (GNH) संबंधी दृष्टिकोण एवं मूल्य पर आधारित है। इसके तहत एक **माइंडफुलनेस सिटी** बनाने पर विचार किया गया है, जिसमें **'शून्य उत्सर्जन'** वाले उद्योगों की स्थापना की जाएगी।
- पूर्वी हिमालय में स्थित **भूटान, चीन और भारत की सीमा से घिरा हुआ एक देश** है। यहां शासन की **संवैधानिक राजतंत्र पद्धति** लागू है, जिसमें एक राजा राज्य का प्रमुख और एक प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है।
- यहां **वज्रयान बौद्ध धर्म को राज्य धर्म** का दर्जा प्राप्त है। इसे तांत्रिक बौद्ध धर्म के नाम से भी जाना जाता है। यह **बौद्ध धर्म का एक उन्नत रूप** है, जो आध्यात्मिक विकास के लिए अनुष्ठानों, दर्शन और करीबी शिक्षक-छात्र संबंध पर जोर देता है।

अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम

लाल सागर में वाणिज्य की सुरक्षा हेतु ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन

18 दिसंबर, 2023 को अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने यमन के ईरान समर्थित 'हूथी विद्रोहियों' (Houthi Rebels) द्वारा मिसाइल और ड्रोन हमलों की एक शृंखला के बाद लाल सागर में वाणिज्य की सुरक्षा के लिए एक बहुराष्ट्रीय अभियान 'ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन' की घोषणा की।

- इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका के **'संयुक्त टास्क फोर्स 153'** (CTF 153) के तहत यूके, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशेल्स और स्पेन शामिल हुए हैं। ये देश दक्षिणी लाल सागर और अदन की खाड़ी में संयुक्त गश्त करेंगे।

प्रतियोगिता क्रॉनिकल

राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं तथा सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं को समर्पित

- ☑ न्यूज बुलेट्स
- ☑ चर्चित शब्दावली
- ☑ राज्य परिदृश्य
- ☑ खेल परिदृश्य
- ☑ लघु संचिका
- ☑ पत्रिका सार
- ☑ संसद प्रश्नोत्तरी
- ☑ परीक्षा सार
- ☑ फैक्ट शीट
- ☑ समसामयिक प्रश्न
- ☑ PIB, AIR, PTI वनलाइनर

प्रतियोगिता क्रॉनिकल नामक यह विशेष खंड 'राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं' तथा अन्य समकक्ष 'सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाओं' को समर्पित है। इस विशेष खंड की शुरुआत दिसंबर 2023 अंक की पत्रिका से की गई थी। यह खंड प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाक्रमों से संबंधित प्रश्नों को ध्यान में रखकर परिकल्पित किया गया है।

इस खंड में राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग व राज्य अधीनस्थ आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं तथा सीडीएस, रेलवे, बैंकिंग आदि अन्य समकक्ष स्नातक स्तरीय परीक्षाओं हेतु समसामयिक घटनाक्रमों का प्रस्तुतीकरण किया जाएगा।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा में पिछले कुछ वर्षों में पूछे जाने वाले करेंट अफेयर्स के प्रश्नों की प्रकृति में व्यापक बदलाव देखा गया है; अब ये प्रश्न समसामयिक घटनाक्रमों की सामान्य अध्ययन पृष्ठभूमि से पूछे जाते हैं। अतः UPSC-CSE हेतु प्रश्नों के अंतरविषयी एवं बहुविषयी प्रकृति के अनुरूप करेंट अफेयर्स के अध्ययन की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए आलेख, इन फोकस, नियमित स्तंभ तथा विशेषांक के रूप में पत्रिका का शुरुआती भाग सिविल सेवा को समर्पित किया गया है।

सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले करेंट अफेयर्स के प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से समसामयिक घटनाक्रमों से ही संबंधित होते हैं तथा इन प्रश्नों की प्रकृति तथ्यात्मक होती है। इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाक्रमों के बिन्दुवार एवं तथ्यात्मक अध्ययन की आवश्यकता है, न कि इसके विश्लेषणपरक अध्ययन की। परीक्षार्थियों की इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम यह नवीन खंड लेकर आए हैं।

न्यूज़ बुलेट्स

राष्ट्रीय परिदृश्य

16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति

- केंद्र ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है
- वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी ऋत्विक रंजनम पांडे आयोग के सचिव होंगे।
- अधिसूचना में कहा गया है कि आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर रिपोर्ट जमा करने की तारीख या 31 अक्टूबर, 2025, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे।
- आयोग 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली 5 वर्ष की अवधि को कवर करते हुए अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 2025 तक उपलब्ध कराएगा। वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है।

वकीलों के स्थगन पर एसओपी हेतु समिति

- सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही के दौरान स्थगन की मांग करने वाले वकीलों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) विकसित करने हेतु न्यायाधीशों की एक समिति का गठन किया है।
- समिति द्वारा इस संबंध में बार काउंसिल के सदस्यों और अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं।
- इससे पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा वकीलों से अपील की गई थी कि वे नए मामलों में स्थगन की मांग न करें, इससे न्यायिक विलंब होता है तथा इस तरह की देरी से नागरिकों का अदालत पर भरोसा खत्म होता है।

NAeG के लिए योजना और वेब-पोर्टल

- 8 दिसंबर, 2023 को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा 'ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार' (NAeG) 2024 हेतु योजना और वेब-पोर्टल को लॉन्च किया गया। इस योजना का उद्देश्य ई-गवर्नेंस कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को पहचानना और बढ़ावा देना, सफल ई-गवर्नेंस समाधानों में नवाचारों को प्रोत्साहित करना है।
- इस वर्ष NAeG-2024 के तहत 16 पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। NAeG पुरस्कार 2024 में ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और स्वर्ण पुरस्कार विजेताओं के लिए 10 लाख रुपये और रजत पुरस्कार विजेताओं के लिए 5 लाख रुपये का प्रोत्साहन शामिल होगा।

प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड

- 1 दिसंबर 2023 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पुणे स्थित सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज (AFMC) को प्रेसिडेंट्स कलर (President's Colour) अवार्ड प्रदान किया।
- राष्ट्रपति ने इस अवसर को चिह्नित करने के लिए एक स्मारक सिक्का (75 रुपये) और एक डाक टिकट जारी किया।
- राष्ट्रपति ने कम्प्यूटेशनल मेडिसिन के लिए सशस्त्र बल केंद्र 'प्रज्ञा' का भी उद्घाटन किया।
- प्रेसिडेंट्स कलर, जिसे 'राष्ट्रपति का चिन्ह' भी कहा जाता है, एक सैन्य इकाई को उसकी अनुकरणीय सेवा, साहस और अनुशासन के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। भारतीय नौसेना पहली भारतीय सशस्त्र सेना थी जिसे 27 मई, 1951 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया था।
- सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज (AFMC) की स्थापना 1 मई, 1948 को विभिन्न रक्षा चिकित्सा संगठनों को विलय करके बीसी रॉय समिति की सिफारिशों द्वारा पुणे में की गई थी।

अयोध्या में हवाई अड्डे सहित विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण

- 30 दिसंबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और महर्षि वाल्मिकी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया।
- अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा 'ग्रीन स्टेशन बिल्डिंग' के रूप में प्रमाणित किया गया है।
- प्रधानमंत्री द्वारा 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
- प्रधानमंत्री द्वारा इस अवसर पर अयोध्या में 15,700 करोड़ रुपये की 46 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया।

पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक

- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 दिसंबर, 2023 को पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की।
- यह बैठक भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा बिहार सरकार के सहयोग से आयोजित की गई।
- पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड राज्य शामिल हैं।
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत वर्ष 1957 में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी।

चर्चित शब्दावली

इंसुक्विक

- हाल ही में, ड्रग फर्म यूएसवी और बायो-टेक कंपनी बायोजेनॉमिक्स ने भारत का पहला बायोसिमिलर इंसुलिन एस्पार्ट 'INSUQUICK' लॉन्च किया है।
- यह तेजी से काम करने वाला इंसुलिन है, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है।
- यह इंसुलिन 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में मधुमेह का इलाज करता है। यह 'मेक इन इंडिया' उत्पाद पर आधारित है।

एक्टोसाईट

- 'एक्टोसाइट' (AKTOCYTE) परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) और आईडीआरएस लैब्स द्वारा विकसित एक न्यूट्रास्युटिकल टेबलेट है। यह रेडियोथेरेपी रोगियों के लिए हैं, जो विशेष रूप से रेडियोथेरेपी-प्रेरित सिस्टिटिस (Cystitis) अर्थात यूरिन में रक्त से पीड़ित पेल्विक कैंसर से पीड़ित हैं।
- 'एक्टोसाइट' को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत संचालित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) से मंजूरी मिल गई है।

रेड स्प्राइट

- हाल ही में, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के अंतरिक्ष यात्री ने एक असामान्य घटना की तस्वीर खींची, जिसे 'रेड स्प्राइट' कहा जाता है। यह असाधारण मौसम संबंधी घटना का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे क्षणिक चमकदार घटना (TLE) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- यह तीव्र थंडरस्टॉर्म विद्युतीकरण के परिणामस्वरूप स्ट्रैटोस्फेरिक/मेसोस्फेरिक गड़बड़ी का संक्षिप्त रूप भी है।

'एयरग्लो'

- हाल ही में, नासा ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISA) से एक तस्वीर साझा की, जिसमें ऊपर चंद्रमा के साथ क्षितिज को रेखांकित करते हुए पृथ्वी की 'एयरग्लो' दिखाई दे रही है।
- एयरग्लो पृथ्वी के वायुमंडल की प्राकृतिक 'चमक (GLOWING)' है, जो हर समय पूरे विश्व में होता है।

कैच डीएनए

- हाल ही में, शोधकर्ताओं ने चूहों में कोलोरेक्टल कैंसर का पता लगाने के लिए बैक्टीरिया शोध आधारित क्रिस्पर (CRISPR) का उपयोग किया।
- 'कैच' (कोशिकीय जांच भेदभावपूर्ण क्षैतिज जीन स्थानांतरण) का वर्णन जर्नल साइंस में प्रकाशित एक शोध लेख में लक्षित क्रिस्पर (CRISPR) के लिए किया गया है।
- 'कैच' को विकसित करने के लिए, शोधकर्ताओं ने फ्री-फ्लोटिंग डीएनए अनुक्रमों का परीक्षण करने और पूर्व निर्धारित कैंसर अनुक्रमों के साथ उनकी तुलना करने के लिए क्रिस्पर तकनीक का उपयोग करके बैक्टीरिया का शोध किया।

कोल्ड मून

- इसे लॉन्ग नाइट्स मून भी कहा जाता है, जो हर साल दिसंबर में पूर्णिमा को दिखती है। दिसंबर की पूर्णिमा उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों की शुरुआत का प्रतीक है, इसे कोल्ड मून, फ्रॉस्ट मून और विंटर मून का नाम दिया गया है।
- इसका नाम मूल अमेरिकी परंपराओं से उत्पन्न हुआ है और मध्य सर्दियों के ठंडे तापमान और ठंडी हवाओं को दर्शाता है।

कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कार्डधारकों के लिए बैंकों के माध्यम से कार्ड-ऑन-फाइल (CoF) टोकनाइजेशन की शुरुआत की।
- यह सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ते हुए वास्तविक कार्ड विवरण को एक अद्वितीय 16-अंकीय टोकन से बदल देता है।
- सीओएफ टोकन, कार्ड जारीकर्ता द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग चैनलों के माध्यम से उत्पन्न किए जा सकते हैं।

द ग्रेट अनकॉन्फॉर्मिटी

- वैज्ञानिकों ने 'स्नोबॉल अर्थ' के दौरान हिमनदों के क्षरण से जुड़ी 'द ग्रेट अनकॉन्फॉर्मिटी' को समझने में प्रगति की है।
- 'स्नोबॉल अर्थ' युग के दौरान हिमनद गतिविधि ने तलछटी रिकॉर्ड में एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा कर दिया, जिससे वैश्विक स्तर पर 3-5 किलोमीटर की चट्टान नष्ट हो गई।

प्लास्टिक रॉक्स

- विश्वभर में प्लास्टिक युक्त एक अजीब और नई तरह की चट्टान पाई गई है। वे मुख्य रूप से मनुष्यों द्वारा छोड़े गए चट्टान और प्लास्टिक पॉलिमर को संपीड़ित करके बनाए गए हैं।
- प्लास्टिक की चट्टानें स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करते हुए माइक्रोबियल समुदायों को बदल देती हैं।

हिमालय काटाबेटिक विंड

- शक्तिशाली हिमालय में एक आश्चर्यजनक घटना सामने आई है, जो वैश्विक जलवायु संकट के प्रभाव को धीमा कर सकती है।
- जब उच्च तापमान, उच्च ऊंचाई वाले बर्फ द्रव्यमान पर पड़ता है, तो 'काटाबैटिक' हवाएं शुरू हो जाती हैं, जो ठंडी हवा को कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ले जाती हैं। ■■

राज्य परिदृश्य

उत्तर प्रदेश

अयोध्या एयरपोर्ट और रेलवे जंक्शन का उद्घाटन

30 दिसंबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उदघाटन किया गया।

- सरकार द्वारा अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल कर "महर्षि वाल्मिकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट" करने की घोषणा की गई है।
- इसके अलावा अयोध्या रेलवे स्टेशन का भी नाम बदलकर 'अयोध्या धाम जंक्शन' किया गया है। अयोध्या के अत्याधुनिक हवाई अड्डे का पहला चरण 1,450 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया गया है।

- हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 6,500 वर्गमीटर है। अयोध्या टर्मिनल भवन का अग्रभाग अयोध्या के श्रीराम मंदिर की वास्तुकला को दर्शाता है।
- टर्मिनल भवन के अंदरूनी हिस्सों को भगवान श्रीराम के जीवन को दर्शाते हुए स्थानीय कला, चित्रों और भित्ति चित्रों से सजाया गया है।
- यह नवनिर्मित हवाई अड्डा मुख्य अयोध्या शहर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है। उसमें आधुनिक निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया है।

देश की पहली एआई सिटी

उत्तर प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) शहर के रूप में विकसित करने को हरी झंडी दे दी है।

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, लखनऊ में एआई सिटी की स्थापना के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPLC) द्वारा कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
- इस पहल का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक संपन्न केंद्र बनाना है, इसके साथ ही अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, अनुसंधान केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों को एकीकृत करना है, ताकि नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और भविष्य के कार्यबल का पोषण किया जा सके।
- सरकार नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में 40 एकड़ जमीन आवंटित करेगी, जिसमें चुने गए डेवलपर को एकमुश्त स्टांप शुल्क छूट सहित अन्य वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। चयनित रियल एस्टेट डेवलपर प्लग-एंड-प्ले सेटअप के साथ कार्यालय बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगा।

गोरखपुर में क्रूज सेवा लेक क्वीन का उद्घाटन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 दिसंबर, 2023 को गोरखपुर के रामगढ़ताल में 'लेक क्वीन क्रूज' (Lake Queen Cruise) सेवा का उद्घाटन किया।

- इस क्रूज सेवा से पर्यटन और रोजगार सृजन का विस्तार होगा।
- लेक क्वीन क्रूज के निर्माण पर 12 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आया है।
- 2,700 वर्ग फीट के क्षेत्रफल वाले क्रूज पर 3 तल बनाए गए हैं और पंचसितारा होटल जैसी सुविधाएं विकसित की गईं हैं।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने राप्ती, सरयू, गंगा और यमुना जैसी नदियों में इनलैंड वाटर वे सेवा शुरू करने के लिए 'इनलैंड वाटर वे एथॉरिटी' का गठन किया है।
- इस एथॉरिटी के गठन से क्रूज सेवा को बढ़ावा मिलेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा।
- वाराणसी से हल्दिया तक गंगा नदी में इनलैंड वाटर वे बनाकर क्रूज चलाया जा रहा है।

अंतर-जनपदीय हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन

हाल ही में, उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पहली अंतर-जनपदीय हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया।

- इस सेवा को प्रारम्भ आगरा शहर से 65 किमी दूर स्थित ऐतिहासिक गांव बटेश्वर में किया गया।
- हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के लिए बटेश्वर गांव का चयन इसकी रणनीतिक स्थिति के कारण किया गया है।
- यह हेलीपैड बटेश्वर को मथुरा में गोवर्धन से जोड़ने वाली उड़ानों के लिए प्रस्थान बिंदु के रूप में कार्य करेगा।
- इस उद्यम को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के आधार पर चलाया जाएगा। इसके माध्यम से क्षेत्र में पर्यटन के नए द्वार खुलने की उम्मीद है।

बिहार

छात्रों की सहायता के लिए मिशन दक्ष

हाल ही में, बिहार सरकार ने राज्य संचालित स्कूलों में शैक्षणिक चुनौतियों का सामना करने वाले लगभग 25 लाख बच्चों के लिए मिशन दक्ष (ज्ञान और कौशल के लिए गतिशील दृष्टिकोण) [Mission Daksh (Dynamic Approach for Knowledge and Skill)] नामक एक नई पहल शुरू की है।

- यह पहल सम्पूर्ण राज्य के कक्षा 3 से 8 के छात्रों को हिंदी, गणित और

- चिराग (अल्मोड़ा, उत्तराखंड) ने तेलंगाना के तरुण एम. को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता।
- जबकि अनमोल (हरियाणा) ने पंजाब की तन्वी शर्मा को हरा कर महिला एकल का खिताब जीता।
- चिराग और अनमोल दोनों ही शटलर पहली बार राष्ट्रीय चैंपियन बने हैं।

राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के विजेता		
स्पर्धा	विजेता	उपविजेता
पुरुष एकल	चिराग सेन	तरुण एम
महिला एकल	अनमोल खरब	तन्वी शर्मा
पुरुष युगल	के पृथ्वी रॉय-सूरज गोला	कृष्ण प्रसाद गरागा-विष्णुवर्धन गौड़ पंजाला
महिला युगल	प्रिया देवी कोन्जेंगबाम-श्रुति मिश्रा	रितिका ठाकर-सिमरन सिंह
मिश्रित युगल	ध्रुव कपिला-तनिषा क्रैस्टो	नितिन कुमार-नवधा मंगलम

सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023

सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का आयोजन 28 नवंबर से 3 दिसंबर, 2023 के बीच लखनऊ के बाबू बनारसी दास बैडमिंटन एकेडमी में किया गया।

- पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल में खिताब के लिए प्रतियोगिता में 19 देशों के लगभग 250 शटलरों ने भाग लिया था।
- भारतीय महिला युगल जोड़ी तनीषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा टूर्नामेंट के फाइनल मैच में जापान की रिन इवांगा और की नाकानिशी की जोड़ी से हार गई।
- इस टूर्नामेंट की शुरुआत उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन (यूपीबीए) द्वारा 1991 में कॉमनवेल्थ गेम चैंपियन सैयद मोदी की याद में 'सैयद मोदी मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट' के रूप में की गई थी।

सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2023 बैडमिंटन विजेता

- **पुरुष एकल:** ची यू जेन (चीनी ताइपे)
- **महिला एकल:** नोजोमी ओकुहारा (जापान)
- **पुरुष युगल:** चूंग होन जियान/हैकाल मुहम्मद (मलेशिया)
- **महिला युगल:** रिन इवानागा/की नाकानिशी (जापान)
- **मिश्रित युगल:** डेजन फर्डिनन्स्याह/ग्लोरिया एमानुएल विदजाजा (इंडोनेशिया)

ओडिशा मास्टर्स-2023

भारत के सतीश कुमार करुणाकरन ने 17 दिसंबर, 2023 को ओडिशा मास्टर्स के ऑल इंडियन पुरुष एकल फाइनल में अपना पहला बीडब्ल्यूएफ सुपर 100 खिताब जीता।

- सतीश कुमार ने विश्व जूनियर चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता आयुष शेट्टी को 21-18 19-21 21-14 से हराकर यह खिताब जीता।
- तनीषा क्रैस्टो और ध्रुव कपिला की भारतीय जोड़ी ने योंग केइ टेरी और टेन वेइ हेन जेसिका की सिंगापुर की जोड़ी को हराकर मिश्रित युगल का खिताब जीता।
- ओडिशा मास्टर्स 2023, बीडब्ल्यूएफ टूर सुपर 100 टूर्नामेंट के रिजल्ट, पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के लिए खिलाड़ियों की क्वालीफाइंग रैंकिंग में गिने जाएंगे।

एथलेटिक्स

विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार-2023

11 दिसंबर, 2023 को विश्व एथलेटिक्स द्वारा मोनाको में अमेरिका के नूह लायल्स को सर्वश्रेष्ठ पुरुष ट्रैक एथलीट, जबकि केन्या के फेथ किपयेगॉन को सर्वश्रेष्ठ महिला ट्रैक एथलीट घोषित किया गया।

- अमेरिकी एथलीट नूह लायल्स ने वर्ष 2023 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं।
- केन्या की एथलीट फेथ किपयेगॉन ने वर्ष 2023 में विश्व रिकॉर्ड के साथ 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किये हैं।
- फेथ किपयेगॉन 2023 में 1500 मीटर और 5000 मीटर के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता रहीं हैं।

विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2023 के अन्य विजेता:

- **एथलीट ऑफ द इयर - विमेंस आउट ऑफ स्टैडिया:** टाइगस्ट अस्सेफा (इथियोपिया)
- **एथलीट ऑफ द इयर - महिला क्षेत्र:** युलिमार रोजास (वेनेजुएला)
- **एथलीट ऑफ द इयर - पुरुष क्षेत्र:** आर्मंड 'मोंडो' डुप्लांटिस (स्वीडन)
- **एथलीट ऑफ द इयर - मेन्स आउट ऑफ स्टैडिया:** केल्विन किप्टम (केन्या)।
- राइजिंग स्टार ऑफ द इयर - फेथ चेरोटिच और इमैनुएल वान्योनी (केन्या)।

क्रिकेट

अंडर-19 एशिया कप 2023

बांग्लादेश ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को फाइनल में 195 रनों से हराकर पहली बार अंडर-19 एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है।

- अंडर-19 एशिया कप 2023 का आयोजन यूएई में 8 से 17 दिसंबर, 2023 को किया गया था।
- बांग्लादेश के आशिकुर रहमान शिबली (149 गेंद पर 129 रन) को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
- आशिकुर रहमान शिबली को एशिया कप की 5 पारियों में दो शतक और दो अर्धशतक सहित 378 रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया।
- अंडर-19 एशिया कप का आयोजन वर्ष 1989 से किया जा रहा है।
- वनडे प्रारूप में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट के अब तक 10 संस्करण खेले जा चुके हैं।
- इस प्रारूप में भारत अब तक सर्वाधिक 8 बार खिताब जीतकर अंडर-19 एशिया कप में सबसे सफल टीम रही है।

विजय हजारे ट्रॉफी 2023

हरियाणा ने राजस्थान को 30 रनों से हराकर पहली बार विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता।

- हरियाणा के सुमित कुमार को 'प्लेयर ऑफ द मैच' और 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया।
- टूर्नामेंट का आयोजन 12 नवंबर से 15 दिसंबर, 2023 के मध्य 6 अलग-अलग शहरों में किया गया।
- टूर्नामेंट में 38 टीमें शामिल थीं, जिन्हें 5 समूहों में विभाजित किया गया था। विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में भी जाना जाता है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत वर्ष 2002-03 में सीमित ओवरों के टूर्नामेंट के तौर पर हुई थी।
- वर्ष 2007 में, भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे के सम्मान में इसका नाम बदलकर "विजय हजारे ट्रॉफी" कर दिया गया।
- यह प्रतियोगिता भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा आयोजित की जाती है।

मुक्केबाजी

आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023

आर्मेनिया के येरेवन में 23 नवंबर से 4 दिसंबर, 2023 तक आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया।

- आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय दल ने 3 स्वर्ण, 9 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 17 पदक प्राप्त किए।

भारतीय पदक विजेताओं की सूची:

- **महिला वर्ग**
- **स्वर्ण:** पायल (48 किलोग्राम), निशा (52 किलोग्राम) और आकांक्षा (70 किलोग्राम)
- **रजत:** अमिषा (54 किलोग्राम), विनी (57 किलोग्राम), श्रुष्टि साठे (63 किलोग्राम), मेघा (80 किलोग्राम) और प्राची टोकस (80 किलोग्राम से ज्यादा)
- **कांस्य:** नेहा लुंथी (46 किलोग्राम), परी (50 किलोग्राम), निधि ढुल (66 किलोग्राम) और कृतिका (75 किलोग्राम)
- **पुरुष वर्ग**
- **रजत:** जतिन (54 किलोग्राम), साहिल (75 किलोग्राम), हार्दिक पंवार (80 किलोग्राम) और हेमंत सांगवान (80 किलोग्राम से ज्यादा)
- **कांस्य:** सिकंदर (48 किलोग्राम)

महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023

विश्व चैंपियन स्वीटी बूरा, राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता जैस्मीन और ओलंपियन पूजा रानी ने महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में अपने-अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किये।

- राष्ट्रीय चैंपियनशिप 22 से 27 दिसंबर, 2023 तक गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, में आयोजित की गई।
- स्वीटी बूरा ने 81 किग्रा भार वर्ग के फाइनल में लालफाकमावी राल्टे को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता।
- जैस्मीन ने 60 किग्रा वर्ग में टोक्यो ओलंपियन सिमरनजीत कौर को 4-3 के अंतर से हराकर स्वर्ण पदक जीता।
- पूजा रानी ने 75 किग्रा वर्ग में नंदिनी को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। कुल 12 भार वर्गों में प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें 300 से अधिक भारतीय मुक्केबाजों ने भाग लिया।

विविध

इटली ने एडमिरल कप 2023 जीता

मिडशिपमैन एवलोन एंटोनियो और मिडशिपमैन क्रिएटी कार्लो लियोनार्डो के नेतृत्व में इटली की टीम ने एडमिरल कप 2023 जीता। भारतीय टीम इस प्रतियोगिता की उपविजेता रही।

- 'एडमिरल कप' सेलिंग रेगाटा के 12वें संस्करण का आयोजन 5-8 दिसंबर 2023 को एझिमाला स्थित भारतीय नौसेना अकादमी (INA) के एट्टीकुलम बीच पर किया गया।
- रूस के सीमैन गोर्कुनोव पेट्र ने पुरुष वर्ग की व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्थान प्राप्त किया।
- ब्रिटेन की ऑफिसर कैडेट लुसी बेल महिला वर्ग की व्यक्तिगत स्पर्धा पर पहले स्थान पर रहीं।
- एडमिरल कप नौकायन प्रतियोगिता में 8 महिलाओं सहित 43 लोगों ने भाग लिया था।
- 2010 में शुरू एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा 2023 के इस संस्करण में 20 देशों तथा भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला की भारतीय टीमों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने 20 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा 9 जनवरी, 2024 को प्रदान किये जाएंगे।

- मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 चिराग चन्द्रशेखर शेट्टी और रंकीरेड्डी सात्विक साई राज को दिया जाएगा।
- 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
- खेल-कूद में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार हेतु 3 खिलाड़ियों को चुना गया है। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी के लिए देश के 3 विश्वविद्यालयों को चुना गया है।अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वालों में इस वर्ष क्रिकेट के एक मात्र खिलाड़ी मोहम्मद शामी हैं।
- राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और सम्मानित करने के लिए प्रति वर्ष प्रदान किये जाते हैं।
- 'मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार' किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले चार वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है।
- 'खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार' पिछले चार वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना के गुण दर्शाने के लिए दिया जाता है।
- 'खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार' लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ■■

लघु संचिका

नियुक्ति

एंड्री राजोएलिना

हाल ही में मेडागास्कर के संवैधानिक न्यायालय ने एंड्री राजोएलिना (Andry Rajoelina) के **राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल** के लिए चुने जाने की पुष्टि की।

- अदालत ने **59% वोटों** के साथ राजोएलिना को विजेता घोषित किया है।
- तीसरे कार्यकाल के लिए राजोएलिना की उम्मीदवारी की आलोचना करने वाले विपक्षी दलों ने अपने समर्थकों से मतदान से दूर रहने का आग्रह किया, जिससे ऐतिहासिक रूप से **46% कम मतदान** हुआ। विपक्षी दलों ने चुनावी निष्पक्षता को लेकर चिंताओं के चलते इसे रद्द करने की मांग की थी।

मनीषा पाढ़ी

हाल ही में, वायु सेना (IAF) की महिला अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को **सहायक-डी-कैंप** (एडीसी) के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्हें मिजोरम के राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कंभमपति ने एड-डी-कैंप नियुक्त किया।

- मनीषा भारत की पहली महिला भारतीय सशस्त्र बल अधिकारी हैं, जिन्हें देश में किसी राज्यपाल के एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया है।
- एड-डी-कैंप राज्य के प्रमुख सहित उच्च पद के व्यक्ति का निजी सहायक या सचिव होता है।
- स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी **2015 बैच** की भारतीय वायु सेना अधिकारी हैं।

कंचन देवी

हाल ही में, मध्य प्रदेश कैडर की 1991 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी कंचन देवी को **भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिदेशक** नियुक्त किया गया है।

- यह **प्रथम अवसर** है, जब किसी महिला अधिकारी को परिषद के इस सम्मानित पद पर नियुक्त किया गया है।
- **भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE):** यह भारत सरकार के **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** के तहत एक **स्वायत्त संगठन** है।
- इसका **मुख्यालय देहरादून** में है तथा इसकी **स्थापना 1986** में की गई थी।
  - आईसीएफआरई वानिकी अनुसंधान करने, वानिकी शिक्षा प्रदान करने जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - आईसीएफआरई भारत में वानिकी अनुसंधान के लिए जिम्मेदार सबसे बड़ा संगठन है।

कैप्टन गीतिका कौल

हाल ही में, कैप्टन गीतिका कौल विश्व के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र 'सियाचिन' में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बन गई हैं।

- कैप्टन गीतिका महिला **सेना चिकित्सक** है तथा इनकी तैनाती भारत के सशस्त्र बलों में लैंगिक समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति मानी जा रही है।
- सियाचिन का उत्तरी हिमालयी क्षेत्र अपने सामरिक महत्व, खराब मौसम और कठिन भूभाग के कारण कठिनाइयां प्रस्तुत करता है।
- यह कराकोरम में सबसे लंबा और विश्व के गैर-ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई 76 किमी. है।
- अक्साई चिन, काराकोरम दर्रा और शक्सगाम घाटी के मध्य स्थित होने के कारण, यह चीन, पाकिस्तान और भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखता है।

समीर शाह

- हाल ही में, **ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (BBC) के नए अध्यक्ष** के रूप में समीर शाह को चुना गया है।
- समीर शाह इस पद के लिए रिचर्ड शाप का स्थान लेंगे। रिचर्ड शाप ने अप्रैल 2023 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
- समीर शाह को टेलीविजन और विरासत की सेवाओं के लिए 2019 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा **कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एंपायर** से सम्मानित किया गया था।

उमा शेखर

उमा शेखर को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ (UNIDROIT) की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है।

- UNIDROIT की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनाव का आयोजन 14 दिसंबर, 2023 को इटली की राजधानी रोम में किया गया था।
- उमा शेखर रोम स्थित इस संगठन की गवर्निंग काउंसिल में स्थान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला हैं।
- UNIDROIT वैश्विक स्तर पर वाणिज्यिक कानून में एकरूपता को बढ़ावा देने पर केंद्रित एक स्वतंत्र अंतरसरकारी संगठन है; जिसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है।

पी. देवस्थली

कमांडर प्रेरणा देवस्थली को भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

- कमांडर देवस्थली, भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े के युद्धपोत का कमान संभालेंगी।

पत्रिका सार

प्राय: ऐसा देखा गया है कि UPSC एवं राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं सहित अन्य समकक्ष एवं सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में योजना, कुरुक्षेत्र एवं विज्ञान प्रगति/साइंस रिपोर्टर जैसी प्रमुख पत्रिकाओं से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हम प्रतियोगी छात्रों के लिए इन पत्रिकाओं के परीक्षोपयोगी बिन्दुओं का प्रस्तुतीकरण कर रहे हैं।

योजना (दिसंबर 2023)

अंतरिक्ष में भारत की ऊंची उड़ान

- **आदित्य एल-1 और चंद्रयान-3** जैसे वर्ष 2023 में संपन्न किए गए महत्वपूर्ण मिशन इसरो द्वारा पहले से ही विकसित 'यूनिवर्सल नेविगेशन गाइडेंस' और 'कंट्रोल प्रणालियों' की आधुनिकतम टेक्नोलॉजी की क्षमता के कारण ही सफल हुए हैं।
- **वर्तमान समय में** इसरो विश्व की उन पांच प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों में शामिल हो गया है, जिनके पास **पृथ्वी के अध्ययन, संचार, नेविगेशन और गृह संबंधी खोजों** की पूर्ण क्षमता है।
- अपनी अनूठी अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली के आधार पर इसरो चार सक्रिय प्रक्षेपण यानों की सहायता से पृथ्वी की **निचली, मध्य तथा उच्च कक्षा** में 500 किलोग्राम से 8000 किलोग्राम तक के पेलोड अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम हो गया है।
- **ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान** (PSLV) के परिवर्तन-समय (टर्न-अराउंड) की सटीकता के कारण इसे विश्व भर में लोकप्रियता प्राप्त हुई है।
- पीएसएलवी **एक ही उड़ान में अनेक उपग्रह प्रक्षेपित** कर सकता है तथा इसकी ऊपरी स्टेज वाले **लिक्विड इंजन को आरंभ एवं बंद** किया जा सकता है।
- **एलएमवी-3** (LMV3) प्रक्षेपण यान में स्वयं को आवश्यकता अनुसार एडजस्ट करने की अद्भुत क्षमता है, इसे भारत में विकसित और निर्मित किया गया है।
- **लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान** (SSLV) छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा विकसित किया गया है, जो मांग आधारित समाधान उपलब्ध कराता है।
- **नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम** (NNRMS) की आधारशिला 1980 के दशक के आरंभ में रखी गई थी, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर जीआईएस एप्लीकेशन (GIS Application) में पृथ्वी अवलोकन (EO) डेटा प्रयोग करना था।
- भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन **उपग्रह प्रणाली** (IRNSS) को **'नाविक'** (NavIC) के रूप में जाना जाता है। यह भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है।
- 'नाविक' (NavIC) द्वारा द्वारा भारत और इसके आस-पास **1500 किलोमीटर** तक के क्षेत्र को कवर किया जाता है।
- **एस्ट्रोसेट** (Astrosat) **भारत की प्रथम अंतरिक्ष वेधशाला** है, जिसे 28 सितंबर 2015 को पीएसएलवी-सी30 (PSLV-C30) रॉकेट द्वारा लांच किया गया था।
- **सितंबर 2022** में एस्ट्रोसेट डेटा का उपयोग करने के लिए 54 देश के करीब 2000 लोगों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- **5 नवंबर, 2013** को मंगल ग्रह के लिए **'मार्स ऑर्बिटर मिशन'** को प्रक्षेपित किया गया था, अप्रैल 2022 में लगभग 8 वर्ष के बाद इस मिशन का पृथ्वी से संपर्क समाप्त हो गया।
- **22 जुलाई, 2008** को भारत के प्रथम अंतरिक्ष यान **'चंद्रयान-1'** को प्रक्षेपित किया गया था, इसके द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी वाली कक्षा में चंद्रमा की परिक्रमा की गई थी।
- **22 जुलाई, 2019** को भारत ने सफलतापूर्वक अपना फॉलोअप मिशन **'चंद्रयान-2'** लांच किया था। इस मिशन में एक ऑर्बिटर (लैंडर) और एक रोवर भेजा गया था, सॉफ्ट लैंडिंग की असफलता के बावजूद इसका ऑर्बिटर अभी तक सक्रिय है तथा डेटा भेज रहा है।
- इसी कड़ी में, **14 जुलाई, 2023** को **'चंद्रयान-3'** मिशन को प्रक्षेपित किया गया, जिसने 23 अप्रैल, 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन किया।
- **'आदित्य एल-1'** भारत का प्रथम मिशन है, जो पूर्ण रूप से सौर विज्ञान पर केंद्रित है। सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना की खोजबीन तथा अध्ययन के उद्देश्य से इसे सात यंत्रों से सुसज्जित किया गया है।

भारत, एक उभरती हुई शक्ति

- भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता तथा वैचारिक एवं क्षेत्रीय मतभेदों के वर्तमान युग में **'ब्रिटेन वुड्स'** संरचनाओं सहित वैश्विक बहुपक्षीय संस्थाएं वैकल्पिक परिणाम देने में विफल रही हैं।
- इन परिस्थितियों में भारत ने **जी-20 का सफल नेतृत्व** करके मूल्य आधारित दृष्टिकोण, वैश्विक सहयोग पर बल देने तथा शांति एवं प्रगति के मानव केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से विश्व के समक्ष एक उदाहरण स्थापित किया है।
- जी-20 के आदर्श वाक्य के रूप में **'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य'** तथा **अफ्रीकी संघ** (AU) को जी-20 में शामिल करने की भारत की प्रतिबद्धता ने इसे वैश्विक दक्षिण के एक सच्चे मित्र के रूप में पहचान दी है।

- 'कृषि उड़ान 2.0' योजना में देश के कुल **58 हवाई अड्डे** शामिल किए गए हैं, इनमें से 25 पूर्वोत्तर, पहाड़ी, आदिवासी क्षेत्रों तथा द्वीपों से, जबकि 33 हवाई अड्डे अन्य क्षेत्रों से शामिल किए गए हैं।
- 'सुगम्य भारत अभियान' दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अनुरूप हवाई अड्डों पर वरिष्ठ लोगों, बच्चों, गर्भवती माताओं और विभिन्न अन्य उपयोगकर्ताओं की हवाई यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए लागू किया गया है।

भारत का उद्योग क्षेत्र

- वर्ष 2021 में आरंभ की गई **'पीएम गति शक्ति योजना'** का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स की कार्यकुशलता में वृद्धि करने तथा खर्चे में कमी करने के साथ अंतर-विभागीय विभाजनों को तोड़ना था।
- 'पीएम गति शक्ति योजना' के **प्रथम घटक** के तहत भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) आधारित प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय मास्टर प्लान के विकास की बात की गई है। वहीं **दूसरी तरफ**, इसका दूसरा पहलू एक स्पष्ट संस्थागत व्यवस्था के निर्माण पर केंद्रित है।
- वर्ष 2022 में आरंभ की गई **'राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति'** (NLP) लॉजिस्टिक्स क्षेत्र हेतु एक अंत:-विषय, क्रॉस-सेक्टोरल, बहु-क्षेत्राधिकार और व्यापक नीतिगत ढांचा प्रस्तुत करती है।
- इस प्रकार, 'राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति' 'पीएम गति शक्ति योजना' की पूरक है।
- **उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग** (DPIIT) द्वारा **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश** (FDI) पर नीतियों को तैयार किया जाता है।
- DPIIT भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रेषित धन के आधार पर, भारत में होने वाले **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश डेटा का रख-रखाव और प्रबंधन** भी करता है।
- जून 2017 में **'विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड'** (FIPB) को समाप्त करने के पश्चात FDI की मंजूरी देने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है।
- अगस्त 2022 से **'विदेशी निवेश सुविधा (FIF) पोर्टल'** को **'नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम'** (NSWS) **के साथ एकीकृत** कर दिया गया है।
- सरकारी मंजूरी की आवश्यकता वाले FDI प्रस्ताव NSWS पोर्टल के माध्यम से दायर किए जाते हैं।
- **FIF का प्रबंधन एवं संचालन भी DPIIT द्वारा** किया जाता है।
- वर्ष 2014 में निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम श्रेणी के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने तथा भारत को विनिर्माण, डिजाइन एवं नवाचार का केंद्र बनाने के लिए **'मेक इन इंडिया पहल'** आरंभ की गई थी।
- वर्तमान में जारी **'मेक इन इंडिया 2.0'** के तहत 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना** (PLI) का उद्देश्य भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ावा देना है। सरकार ने 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए PLI योजनाओं की घोषणा की है।
- **वर्ष 2016** में आरंभ की गई **'स्टार्टअप इंडिया पहल'** का उद्देश्य नए स्टार्टअप्स के विकास के अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करके उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देना है।
- उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा 15 मई, 2023 तक 674 जिलों में 57 क्षेत्रों के कुल 99,371 स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई है।
- **DPIIT द्वारा** स्टार्टअप्स की फंडिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए **10,000 करोड रुपए** के कोष के साथ **'फंड आफ फंड्स'** की स्थापना की है।
- वर्ष 2021 में **'सार्वजनिक उद्यम विभाग'** को **वित्त मंत्रालय के तहत स्थानांतरित** कर दिया गया।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा औपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को MSME की औपचारिक दायरे में लाने के लिए जनवरी, 2023 में **'उद्यम असिस्ट प्लेटफार्म'** आरंभ किया है।
- भारतीय MSME क्षेत्र 6 करोड़ से अधिक उद्यमों के साथ अर्थव्यवस्था के एक अत्यधिक जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है।
- MSME क्षेत्र भारत के **सकल घरेलू उत्पाद में 27% तथा निर्यात में लगभग 44%** का योगदान करने के साथ देशभर में लगभग **11.10 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार** भी प्रदान करता है।
- इस प्रकार, **कृषि के पश्चात MSME क्षेत्र ही** ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और तुलनात्मक रूप से कम पूंजी लागत पर स्वरोजगार के अवसर पैदा करता है।
- MSME की संशोधित परिभाषा के अनुसार MSME के पंजीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जुलाई, 2020 से **'उद्यम पंजीकरण पोर्टल'** संचालित किया जा रहा है।
- संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित **'खादी और ग्रामोद्योग आयोग'** MSME मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संगठन है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में प्रयासरत है।
- **भारत 50** मिलियन से अधिक स्पिंडल और 8,42,000 रोटर्स की स्थापित क्षमता वाला 3,400 कपड़ा मिलों के साथ **दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग क्षेत्र** है।
- मूल्य के संदर्भ में भारतीय कपड़ा उद्योग कुल उद्योग **उत्पादन में 7%, भारत के GDP में 2% तथा देश के निर्यात आय में 15%** का योगदान देने के साथ लगभग **45 मिलियन से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप में रोजगार** प्रदान करता है।
- भारत में वर्ष 2013-14 से कच्चे इस्पात के उत्पादन और क्षमता में निरंतर वृद्धि देखी गई है। वर्तमान में **भारत की कच्चे इस्पात की क्षमता बढ़कर 142 मीट्रिक टन** हो गई है तथा भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए कच्चे इस्पात का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है।
- **उर्वरक विभाग 'रसायन और उर्वरक मंत्रालय'** के तहत आता है, इसका **उद्देश्य** किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
- **भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग** मात्रा के हिसाब से विश्व भर में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। पिछले 9 वर्षों में यह क्षेत्र 6.4% की वृद्धि के साथ लगातार बढ़ रहा है।
- **वर्ष 2022-2023** के लिए फार्मास्यूटिकल उद्योग का **कुल वार्षिक कारोबार 3,79,450 करोड रुपए** आंकलित किया गया था।

- **भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण** (GSI) देश का प्रमुख पृथ्वी विज्ञान संगठन (1851 में स्थापित) है। यह सरकार को उद्योग और भू-वैज्ञानिक क्षेत्र के लिए बुनियादी पृथ्वी विज्ञान संबंधी जानकारी उपलब्ध कराता है।
- **GSI इसकी वर्तमान गतिविधियों में** सतह मानचित्रण, हवाई और सुदूर संवेदन संवेक्षण, अपतटीय सर्वेक्षण, खनिज और ऊर्जा संसाधनों की खोज, इंजीनियरिंग भू-विज्ञान, भू-तकनीकी जांच, भू-पर्यावरणीय अध्ययन, जल संसाधनों का भू-विज्ञान, अनुसंधान और विकास तथा सूचना सेवाएं शामिल हैं।

कृषि और ग्रामीण विकासः प्रमुख पहल और उपलब्धियां

- कृषि के विकास हेतु **'कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय'** को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए **1,25,026 करोड़ रुपए** आवंटित किए गए हैं; जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से **5% अधिक** है।
- सरकार ने **कृषि ऋण** का **लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड रुपए** कर दिया है। साथ ही, नई योजना **'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना'** आरंभ करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
- **3 जुलाई, 2023** को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा **17वीं 'भारतीय सहकारी कांग्रेस'** को संबोधित करते हुए कहा गया था कि सरकार कृषि और किसानों पर औसतन सालाना 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है।
- **ग्रामीण विकास मंत्रालय** को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए **1,59,964 करोड़ रुपए** आवंटित किए गए हैं।
- बजट में **प्रधानमंत्री आवास योजना** (ग्रामीण और शहरीकरण घटकों को मिलाकर) पर परिव्यय **66% बढ़कर 79,590 करोड़ रुपए** कर दिया गया है।
- वर्ष 2023-24 के बजट में बड़े उत्पादक समूहों के गठन के माध्यम से **ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों के सशक्तीकरण** की भी घोषणा की गई थी।
- भारत ने विशेष रूप से राष्ट्रीय संदर्भ में सम्मान व्यक्त करने के लिए मोटा अनाज का नाम बदलकर **'श्री अन्न'** कर दिया है।
- देशभर में जारी कई प्रचारात्मक और सहायक योजनाओं के कारण **मोटा अनाज की घरेलू खपत बढ़कर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 14 किलोग्राम** हो गई है, जो पहले 3 किलोग्राम से भी अधिक नहीं थी।
- भारत ने वैश्विक परिदृश्य में 'श्री अन्न' की अपार संभावनाओं को सामने लाने के लिए नई दिल्ली में **'ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस'** का आयोजन (मार्च 2023) किया था।
- पिछले वर्ष की तुलना में देश में **खाद्यान्न उत्पादन में 4%** (14 मिलियन टन) से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इसी प्रकार, **बागवानी उपज के उत्पादन में एक प्रतिशत** (5 मिलियन टन) से अधिक की वृद्धि हुई है।
- सरकार द्वारा **विपणन सीजन 2024-25 में** अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की घोषणा गई है। **MSP में सर्वाधिक वृद्धि मसूर के** लिए **425 रुपए प्रति क्विंटल** की गई है।
- मसूर के पश्चात **रेपसीड तथा सरसों** (200 रुपए प्रति क्विंटल), **गेहूं तथा कुसुम** (150 रुपए प्रति क्विंटल), **जौ** (115 रुपए प्रति क्विंटल) तथा **चना** (105 रुपए प्रति क्विंटल) की MSP में भी वृद्धि की गई है।
- इस वर्ष (2023) सरकार द्वारा **'सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना'** की सुविधा की घोषणा की गई है।
- **इस योजना में** प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के स्तर पर विभिन्न प्रकार के **कृषि बुनियादी ढांचे** (गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयों) की स्थापना को शामिल किया गया है।
- सरकार द्वारा बजट प्रस्ताव (2023-24) के अनुसार **'पीएम प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन, अवेयरनेस जेनरेशन, न्यूरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ' (पीएम-प्रणाम) योजना** को मंजूरी दे दी गई है।
- **'पीएम-प्रणाम'** योजना योजना का **उद्देश्य** धरती मां के स्वास्थ्य को बचाने के लिए उर्वरकों के टिकाऊ एवं संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना, वैकल्पिक उर्वरकों एवं वैकल्पिक खेती को अपनाना तथा संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को लागू करना है।
- सरकार द्वारा जैविक उर्वरकों विशेष रूप से **'गोबरधन पहल'** के तहत संयंत्रों में उत्पादित खाद के क्षेत्र में अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 1500 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से बाजार विकास सहायता को भी मंजूरी दी है।
- **वर्ष 2021 में नैनो यूरिया** के उत्पादन को **मंजूरी** दी गई थी। इस वर्ष (2023) तक देश में लगभग 17 करोड़ नैनो यूरिया बोतलें बनाने का बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया गया है।
- सरकार **किसान ऋण पोर्टल** अथवा **किसान क्रेडिट कार्ड** के माध्यम से किसानों को 'संशोधित ब्याज सहायता योजना' के तहत कृषि ऋण का लाभ उठाने के लिए प्रेरित कर रही है।
- **1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2023** तक **'घर-घर केसीसी अभियान'** आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य **'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना'** के लगभग 1.5 करोड़ लाभार्थियों को जोड़ना है, जो अभी तक KCC योजना से नहीं जुड़े हैं।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने प्रमुख कार्यक्रम **'दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन'** (DAY-NRLM) के तहत **2 करोड़ 'लखपति दीदीयों- एसएचजी दीदीयों'** को सक्षम बनाने के लिए विशेष अभियान आरंभ किया है।
- सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए बाजार समर्थन को मजबूत करने की दिशा में एक अभिनव **'ई-सरस मोबाइल एप्लीकेशन'** लॉन्च किया है।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1 फरवरी से 15 अगस्त 2023 के मध्य लखनऊ में अमृत महोत्सव के तहत **'50 हजार ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना'** अभियान आयोजित किया गया था।
- जल जीवन मिशन के तहत **13 करोड़ घरों में नल का पानी उपलब्ध** कराने के **कनेक्शन प्रदान** करने का लक्ष्य हासिल किया है।
- सरकार ने अगले तीन वर्षों में (2023-24 से 2025-26) **75 लाख एलपीजी कनेक्शन** जारी करने के लिए **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार** को मंजूरी दी है।

कुरुक्षेत्र (दिसंबर 2023)

आत्मनिर्भर होते गांवः पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका

- भारत की लगभग 68% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और लगभग **51% कार्यबल** कृषि से संबंधित गतिविधियों में संलग्न है।
- **15वें वित्त आयोग** के तहत वर्ष 2020-21 के लिए **60,750 करोड रुपए** एवं वित्त वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए **2,36,805 करोड़ रुपए** का अनुदान 28 राज्यों को सभी त्रि-स्तरीय पंचायतों तथा परंपरागत स्थानीय निकायों और छठी अनुसूची क्षेत्रों के लिए आवंटित किया गया है।
- केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान का प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष आवंटन **12वें वित्त आयोग** (2005-10) में **54 रुपए से बढ़कर 15वें वित्त आयोग** (2021-26) में 674 रुपए हो गया है।
- सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीयकृत करके, देश की लगभग 2.5 लाख पंचायतों ने अपने गांवों को **स्थानीय स्तर पर निर्धारित गतिविधियों से संतृप्त करने का संकल्प** लिया है। इसकी प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के तहत लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करके उनके क्षमताओं में वृद्धि की जा रही है।
- वर्तमान में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उत्पन्न **'स्वयं के राजस्व स्रोत'** (Own Source Revenue: OSR) कुल राजस्व का औसतन केवल 6% से 7% है। इससे ज्ञात होता है कि ग्रामीण भारत में स्वयं के राजस्व स्रोत बढ़ाने की पर्याप्त क्षमता है।
- **'ई-पंचायत' राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना** (एनईजीपी) के तहत पंचायती राज संस्थाओं में प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिक जन-भागीदारी के साथ अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी स्वशासन विकसित करने के लिए निर्मित किया गया एक सार्थक और दूरगामी मिशन है।
- इस परियोजना का **उद्देश्य** देश भर की 2.5 लाख से अधिक पंचायतों की आंतरिक कार्य प्रक्रिया को स्वचालित करना है।
- **ग्राम मानचित्र वर्ष 2019 में लांच** किया गया था। इस अनुप्रयोग को विभिन्न मंत्रालयों के साथ-साथ जिला अस्पतालों, सीएससी, पीएससी और उप-केंद्रों, बैंक शाखाओं, एटीएम, पत्राचार आदि जैसी सुविधाओं के डेटा के साथ एकीकृत किया जा रहा है।
- एक कार्य आधारित अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के रूप में **'ई-ग्राम स्वराज'** को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 24 अप्रैल, 2020 लॉन्च किया गया था।
- पंचायतों के द्वारा की जाने वाली खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ई-ग्राम स्वराज (ईजीएस) को गवर्नमेंट **ई-मार्केटप्लेस** (GeM) के साथ एकीकृत किया गया है।
- प्रधानमंत्री द्वारा 24 अप्रैल, 2023 को रीवा, मध्य प्रदेश में **'ई-ग्राम स्वराज जैम पोर्टल'** को लांच किया गया। यह एकीकरण पंचायतों को ई-ग्राम स्वराज प्लेटफार्म का लाभ उठाते हुए जैम (GeM) के माध्यम से अपना सामान और सेवाएं खरीदने में सक्षम बनाएगा।
- भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की विशाल संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, पंचायती राज मंत्रालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में **'ग्राम ऊर्जा स्वराज'** के विजन को बढ़ावा देने का प्रयास किया है।
- **'ग्राम ऊर्जा स्वराज' का दृष्टिकोण** नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्रामीण आबादी की सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को समायोजित करने और संबोधित करने का एक प्रयास है।
- 24 अप्रैल, 2020 को आरंभ की गई **'स्वामित्व योजना'** का उद्देश्य, बसे हुए ग्रामीण इलाकों में जिनके पास अपने घर हैं, ऐसे **ग्रामीण घर के मालिकों को 'अधिकार का रिकॉर्ड'** प्रदान करना और **संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करना** है, जो राज्य राजस्व या पंचायती राज अधिनियमों द्वारा समर्थित हैं।
- **'स्वामित्व योजना'** के तहत **ड्रोन सर्वे एवं क्रॉस ओरिजिनल संसाधन साझाकरण** (CORS) तकनीक से निर्मित **उच्च रेजोल्यूशन मानचित्र** (5 सेमी. सटीकता) पंचायतों के लिए अत्यधिक मूल्यवान हैं।
- इन मानचित्रों का उपयोग **संपत्ति रजिस्टरों को अद्यतन करने और संपत्तियों की सटीक तथा अद्यतन जानकारी प्राप्त करने** के लिए किया जा सकता है। इससे पंचायतों को संपत्ति कर क्षमता का आकलन करने का तेज और सटीक उपाय मिल सकेगा।

आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम

- **जनवरी 2018** में लॉन्च किया गया **'आकांक्षी जिला कार्यक्रम'** (ADP) का **उद्देश्य** देश आगे ले जाने के लिए 100 सबसे अधिक पिछड़े जिलों के विकास को तीव्र करना था।
- इसे प्राप्त करने के लिए **नीति आयोग ने 'आकांक्षी जिला फ्रेमवर्क'** तैयार किया है। इसके तहत राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में अविकसित जिलों (जिन्हें आकांक्षी जिला-एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नाम दिया गया) की पहचान करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।
- **'आकांक्षी जिला कार्यक्रम'** के तहत जारी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप अनेक जिलों में कई **प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों ने महत्वपूर्ण प्रगति** की है और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को स्थानीय बनाने में मदद की है।
- 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' के तहत **स्वास्थ्य संकेतकों में भी सुधार** देखने को मिला है। प्रसवपूर्व देखभाल पंजीकरण में उत्तर प्रदेश और बिहार के आकांक्षी जिलों में 36% से 56% तक सुधार हुआ है।
- **जनवरी, 2023 में 'आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम'** (ABP) आरंभ किया गया। ADP की तर्ज पर ABP का उद्देश्य अविकसित ब्लॉकों में योजनाओं की पहुंच में वृद्धि करना है।
- ABP के तहत **500 आकांक्षी ब्लॉकों का चयन** राज्यों के परामर्श से एक अंतर-मंत्रालय समिति द्वारा किया गया है। ये ब्लॉक 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 329 जिलों में स्थित है।

किसानों का तकनीकी सशक्तीकरण

- देश में **'लैब टू लैंड' प्रयासों** से किसानों को तकनीकी रूप से समृद्ध बनाने के साथ-साथ प्रयोगशालाओं में किए जा रहे अनुसंधानों और संसाधनों को सीधे गांवों तक पहुंचाया जा रहा है।

- किसान समुदाय में तकनीकी आत्मनिर्भरता को उत्प्रेरित करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए **वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद** (CSIR) के 'अरोमा और पुष्प खेती मिशन' में सुगंधित फसलों की खेती आरंभ की गई है।
- **अरोमा मिशन** के तहत **6,000 हेक्टेयर को खेती के दायरे में** लाया गया है, जिसमें **46 जिले** शामिल हैं। लगभग 44,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया, 231 डिस्टलेशन इकाइयां स्थापित की गईं और 500 टन आवश्यक तेल तैयार किया गया है।
- **दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत गेंदे के तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश** है। सुगंधित तेल उत्पादन के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में उगायी जाने वाली जंगली गेंदे की **'टैजेटिस माइन्यूटा'** प्रजाति किसानों के लिए लाभ का सौदा साबित हो रही है।
- CSIR द्वारा चयनित गांवों में जल संसाधन बढ़ाने के लिए **ग्राम स्तरीय जल प्रबंधन योजनाओं** को विकसित करने के लिए एक **मिशन मोड परियोजना** का नेतृत्व किया जा रहा है।
- **'जल जीवन मिशन'** के तहत जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से उत्तर-पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्रों में **उच्च-रिजॉल्यूशन एक्विफर मैपिंग और प्रबंधन मिशन** आरंभ किया गया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी उन्नति के लिए **'टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फॉर रूरल एरियाज'** (TARA) योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसका **उद्देश्य** मुख्य रूप से ग्रामीण अनुप्रयोग और सामाजिक लाभ के लिए अनुकूल अनुसंधान को प्राथमिकता और प्रोत्साहन देना है।
- हाल ही में **जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले के पल्ली गांव** को देश का पहला **'कार्बन न्यूट्रल'** गांव घोषित किया गया है। **पल्ली में 500 केवी क्षमता का सौर संयंत्र स्थापित** किया गया है, जिससे कि यह गांव ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है।

उद्योगों से मजबूत होती आत्मनिर्भर गांव की संकल्पना

- **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय** के आंकड़ों के अनुसार **बीते 9 वर्षों** (2014-15 से 2022-23) के बीच **कृषि** (वानिकी व मत्स्य पालन सहित) **की औसत विकास दर 3.7 फीसदी** रही है।
- **सांख्यिकी मंत्रालय** की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के **कुल 2.46 लाख** से ज्यादा कारखानों में से 1.03 लाख, यानी करीब 41 फीसदी कारखाने ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं।
- सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार **633 लाख से कुछ ज्यादा औद्योगिक इकाइयां** (51 फीसदी) ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं। इनमें अकेले सूक्ष्म उद्यमों की हिस्सेदारी 324 लाख की है।
- सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम जहां **11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार** मुहैया कराते हैं, उनमें से लगभग पांच करोड़ रोजगार ग्रामीण इलाकों में हैं।
- **खादी और ग्रामोद्योग आयोग** (KVIC) कपड़े सहित विभिन्न तरह के उत्पादों की बड़े पैमाने पर आपूर्ति कर रहा है। वर्ष 2013-14 में खादी का उत्पादन 811 करोड़ रुपये का था, जो 2022-23 में 3 गुना से भी अधिक बढ़ोत्तरी करके 2916 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
- **KVIC द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम** से 2013-14 के 5.6 लाख नए रोजगार अवसरों की तुलना में **2022-23 में कुल 9.5 लाख रोजगार के अवसर** सृजित किए गए।
- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम** (PMEGP) के तहत **80 प्रतिशत से** अधिक **इकाइयां ग्रामीण इलाकों में** स्थापित की जाती हैं, जिनमें से आधे से अधिक की देखरेख अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों द्वारा की जाती है।
- **25 सितंबर, 2014** को लांच की गई **'दीनदयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना** (DDU-GKY) **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है।

'लखपति दीदी' एक अनूठी पहल

- लखपति दीदी पहल **गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वरोजगार और कौशलयुक्त रोजगार** के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है।
- यह योजना महिलाओं को आवश्यक कौशल से लैस करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए तैयार की गई है, जो **सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त** करती है।
- **'लखपति दीदी' योजना का उद्देश्य** दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत आने वाले **10 करोड़ स्वयं सहायता समूहों** के बड़े परिवार की कम-से-कम दो करोड़ दीदियों को जल्दी से जल्दी सक्षम बनाना है।
- **स्वयं सहायता समूह** समुदाय-आधारित संगठन होते हैं, जो व्यक्तियों के समूह (मुख्य रूप से महिलाओं) द्वारा गठित होते हैं, ये अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक या विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं।
- **'लखपति दीदी' पहल** का कार्यान्वयन दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के दायरे में आता है।
- यह योजना **भारत सरकार का एक प्रमुख ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम** है और आज यह ग्रामीण गरीबों की आजीविका में सुधार के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहल बन गई है।
- मिशन के तहत सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) के 742 जिलों में **फैले 7,091 ब्लॉकों को कवर किया है।**
- मिशन के तहत, **लगभग 9.54 करोड़ महिलाएं 87.39 लाख स्वयं सहायता समूहों** (SHG) का हिस्सा हैं।

डिजिटल रूप से सशक्त गांव की ओर

- **संयुक्त राष्ट्र** के अनुमान के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक खाद्य प्रणाली को पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाए बिना वर्ष **2050 तक 9 अरब** से अधिक लोगों का भरण-पोषण करने में सक्षम होना चाहिए।
- **डिजिटलीकरण** इस दिशा में एक समाधान के रूप में उभरा है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों के समावेशन द्वारा चिह्नित **औद्योगिक क्रांति 4.0** ऐतिहासिक संस्थाओं के विपरीत परिवर्तनकारी क्षमता रखती है।
- कृषि क्षेत्र में समानांतर रूप से डिजिटलीकरण पर आधारित **'कृषि 4.0'** के रूप में नवीन क्रांति आरंभ हो रही है।

- **'कृषि 4.0'** में न केवल **पैराडाइम शिफ्ट डिजिटलीकरण, स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता** को एकीकृत किया जा रहा है, बल्कि यह फसल और पशुधन उत्पादन से लेकर निराई, कीट नियंत्रण और कटाई जैसी कई कृषि एवं पर्यावरणीय चुनौतियों को भी संबोधित करती है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट सेवाओं एवं बुनियादी ढांचे** का समावेशन न केवल जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, बल्कि इससे आर्थिक अवसरों का भी सृजन होता है।
- उद्यमिता को बढ़ावा देकर **डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर गांव** एक आत्मनिर्भर तथा तकनीकी रूप से उन्नत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करता है, इससे ग्रामीण क्षेत्र नवाचार एवं प्रगति के संपन्न केंद्र के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं।
- **नीति आयोग ने 'सभी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' पहल** आरंभ की है, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, स्मार्ट शहर एवं बुनियादी ढांचा तथा परिवहन के साथ-साथ कृषि को भी महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान मिली है।
- **आत्मनिर्भर भारत निधि (SRI)** आत्मनिर्भर भारत के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह निधि एक **मदर फंड-डॉटर फंड संरचना को नियोजित** करती है, जो एमएसएमई के लिए विकास पूंजी का सतत प्रवाह सुनिश्चित करता है।
- फिनटेक कंपनियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे की स्थापना तीव्र गति से की जा रही है। इनके द्वारा डिजिटल बिल भुगतान, मोबाइल बैंकिंग तथा नेट बैंकिंग जैसी सुविधाओं के विकास पर जोर दिया जा रहा है।
- **'ग्रामीण ई-कॉमर्स'** की अवधारणा मुख्यधारा के ई-कॉमर्स से अलग है। 'ग्रामीण ई-कॉमर्स' ग्रामीण उत्पादों के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदान करती है। इसका **उद्देश्य** ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी बाजारों से जोड़ना और आय के स्तर को बढ़ाना है।

गांवों में आर्थिक विकास को बढ़ावा

- भारतीय **गांवों की आत्मनिर्भरता** का विचार **सर्वप्रथम 1830 में सर चार्ल्स मेटकॉफ** द्वारा प्रस्तुत किया गया था। **महात्मा गांधी** ने यथार्थवादी तरीके से **'ग्राम स्वराज'** की कल्पना की थी।
- वर्ष **2023-24 में, ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1,59,964 करोड़ रुपये** आवंटित किए गए हैं, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) जैसे कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है।
- वर्ष **2023-24 के बजट में** फ्लैगशिप कार्यक्रम **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** (NRLM) के लिए आवंटन 13,336 रुपये से बढ़ाकर 14,129 करोड़ रुपये कर दिया गया।
- **'कृषि'** जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख विकास कारक है, को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बजट में लगभग **1.25 लाख करोड़ रुपये** आवंटित किए गए।
- **जल जीवन मिशन**, जिसका लक्ष्य हर घर में सीधे जल आपूर्ति प्रदान करना है, को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए **70,000 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ आवंटन** प्राप्त हुआ। इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के लिए 77,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
- **वर्ष 2014** में शुरू की गई **दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना** (DDU-JKY) विशिष्ट रूप से गरीब परिवारों के 15 से 35 वर्ष की आयु के ग्रामीण युवाओं पर केंद्रित है और इस कार्यक्रम में अब तक 14.51 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।
- **ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान** (RSETI) योजना में, बेरोजगार ग्रामीण युवाओं, विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे के युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और उन्हें नवीनतम प्रौद्योगिकियों से अवगत रखने के लिए समय-समय पर कौशल उन्नयन के लिए विकास सहायता प्रदान की जाती है।
- केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए **4,800 करोड़ रुपये** के वित्तीय आवंटन के साथ एक नई केंद्र प्रायोजित योजना- **'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम'** को भी मंजरी दे दी है, इसका **उद्देश्य** उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना है।
- **भारतीय वन सर्वेक्षण (2019)** का अनुमान है कि कुल 6,50,000 गांवों में से लगभग **26% को वन सीमांत गांवों** के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जहां वन महत्वपूर्ण सामाजिक-सांस्कृतिक और आजीविका की जरूरतों को पूरा करते हैं।
- **पंचायत प्रावधानों का अधिनियम (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996** अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों और सभाओं को लघु वन उपज के स्वामित्व एवं ग्रामीण बाजारों का प्रबंध करने तथा स्थानीय योजनाओं एवं संसाधनों पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान करता है।
- वर्तमान में, **यात्रा और पर्यटन उद्योग 14 मिलियन लोगों को रोजगार** प्रदान करता है, जिसके 2027 तक 25% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाने की उम्मीद है।
- **विश्व पर्यटन संगठन** (UNWTO) द्वारा दुनिया भर के **32 गंतव्यों को 'सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2022' के रूप में नामित** किया गया है।
- केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2023 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा स्थापित कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए **'कृषि त्वरक निधि'** पेश की गई थी।
- **'कल के गांव'** एक ऐसी पहल है, जिसे **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम** (UNDP) ने ग्रामीण क्षेत्रों में असमानताओं को कम करने और लिंग संवेदनशील डिजिटलीकरण विकसित करने के लिए **तुर्की स्थित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ट्रेंडयोल** के साथ मिलकर डिजाइन किया है।

आत्मनिर्भर गांव में कृषि की भूमिका

- **सहकारिता** पारस्परिक सहयोग के माध्यम से सामूहिक और व्यक्तिगत लाभ की भावना पर आधारित है।
- **सहकारिता ग्रामीण भारत को उद्यमोन्मुखी बनाकर** न केवल समग्र विकास कर सकती है, बल्कि शहरों पर आबादी के अनावश्यक दबाव को कम कर शहरी आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सक्षम है।
- **'वोकल फॉर लोकल'** स्थानीय उत्पादों और व्यवसायों को बढ़ावा देकर उनकी विशिष्टता को देश-विदेश तक पहुंचाने का अभियान है। इसका **उद्देश्य** देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है।

- **भारत सरकार** ने जमीनी स्तर पर सहकारिता को मजबूत करने के लिए **अगले 3 वर्षों में 63 हजार प्राथमिक साख सहकारी समितियों** (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण हेतु **2,516 करोड़ रुपये** का बजट आवंटित किया है।
- **कृषि स्टार्टअप्स** देश की कृषि उद्यमिता में आमूलचूल परिवर्तन ला रहे हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि, अभी देश में मान्यता प्राप्त **एग्रीटेक स्टार्टअप्स 1,485** हैं; किंतु कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है।
- **कृषि शिक्षा और विस्तार सेवाओं** के बल पर पिछले 7 दशकों में हमने खाद्यान्न उत्पादन में 6.5 गुना, बागवानी उत्पादन में 13 गुना, दूध उत्पादन में 13 गुना, मछली उत्पादन में 21.6 गुना, अंडों के उत्पादन में 70.7 गुना वृद्धि अर्जित की है, जिसका राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा पर स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित हुआ है।
- देश में **1950 के दशक की शुरुआत से खाद्यान्न की पैदावार बढ़कर** 50.82 मिलियन टन से वर्ष 2022-23 में **329.68 मिलियन टन हो गई** है, यानी पिछले **7 दशकों में 6.5 गुना वृद्धि** हुई है।
- वर्ष 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण में चेतावनी दी गई थी कि **जलवायु परिवर्तन** के कारण वार्षिक **कृषि आय में 15% से 18% और गैर-सिंचित क्षेत्रों की उपज में 20% से 25% तक की कमी आ सकती** है।
- **फोर्ब्स का अनुमान** है कि एआई और मशीन लर्निंग सहित स्मार्ट **कृषि पर वैश्विक खर्च** वर्ष **2025 तक तीन गुना** बढ़कर **15.3 बिलियन डॉलर** हो जाएगा; जबकि कृषि में एआई बाजार का आकार 20 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) की गति से बढ़कर वर्ष 2026 तक 2.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा।
- हालांकि **भारतीय कृषि तकनीक बाजार का वर्तमान मूल्य 225 मिलियन यूएस डॉलर** है, जिसके वर्ष 2022 से 2028 के दौरान 24 प्रतिशत CAGR से बढ़ने का अनुमान है।
- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान **कृषि में ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ब्लॉकचेन, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस आदि नई तकनीकों को पेश करने** के लिए राज्यों को क्रमशः 1756.3 करोड़ और 2422.7 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की थी।

पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगर

- **हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र असंगठित आर्थिक गतिविधियों** में आते हैं, इनसे लगभग 65 लाख दस्तकारों और बुनकरों को आजीविका प्राप्त होती है। इनमें देश भर में हथकरघा क्षेत्र में कार्यरत **25.46 लाख महिलाएं और हस्तशिल्प क्षेत्र में कार्यरत 20 लाख महिलाएं** शामिल हैं।
- **हथकरघा** हाथ से संचालित करघे का उपयोग करके कपड़ा बुनने की प्रक्रिया है, जबकि **हस्तशिल्प** पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके कुशल कारीगरों द्वारा बनाई गई वस्तुएं होती हैं।
- भारत के हथकरघा क्षेत्र में 35 लाख से अधिक हथकरघा कामगार और 27 लाख हस्तशिल्प कारीगर काम करते हैं।
- प्रधानमंत्री द्वारा **7 अगस्त, 2015** को भारत की विकास यात्रा में हथकरघा बुनकरों के योगदान को रेखांकित करते हुए इस दिन को **'राष्ट्रीय हथकरघा दिवस'** के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी।
- सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले हथकरघा उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए **'इंडिया हैंडलूम ब्रांड'** योजना शुरू की गई है। इसका **उद्देश्य** उत्पादों को प्रोत्साहित करने और उन्हें अलग पहचान देने के साथ ही उत्पादों के टिकाऊपन और विशिष्टता को सामने रखना है।
- **अप्रैल 2023** में वित्त मंत्रालय द्वारा बिचौलियों की भूमिका समाप्त करते हुए **35 लाख** से अधिक हथकरघा बुनकरों और **27 लाख हस्तशिल्प कारीगरों** के उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के लिए **'ई-कॉमर्स पोर्टल'** बनाया गया है।

साइंस रिपोर्टर (दिसंबर 2023)

पेट्रीफाइड लकड़ी

- **पेट्रीफाइड लकड़ी एक प्रकार का जीवाश्म** है, जो तब बनता है, जब लकड़ी में कार्बनिक पदार्थ को खनिजों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जिससे **लकड़ी की मूल संरचना संरक्षित करते हुए यह पत्थर में बदल** जाती है।
- लकड़ी के पेट्रीफाइड बनने के लिए **पहला कदम** यह है कि पेड़ ज्वालामुखी की राख या किसी अन्य पदार्थ की रेत में दब जाते हैं और इस कारण उन्हें **सड़ने में लंबा समय** लगता है।
- पेट्रीफाइड लकड़ी कई अलग-अलग रंगों में पाई जा सकती है। पत्थरों का रंग कैसा होगा, यह मिट्टी में मौजूद रसायनों पर निर्भर करता है।
- पेट्रीफाइड लकड़ी को **हजारों वर्षों तक संरक्षित करने** तथा सामान्य क्षय से बचाने के लिए **भौगोलिक परिस्थितियां उपयुक्त** होनी चाहिए।

प्रिंस रूबर्ट ड्रॉप्स

- **प्रिंस रूपर्ट ड्रॉप्स** [जिसे डच आंसू या बटावियन आंसू के रूप में भी जाना जाता है] ठंडे पानी में पिघले हुए गिलास को टपकाने से बने कठोर कांच के गोले हैं। यह एक लंबी, पतली पूंछ के साथ टैडपोल के आकार की बूंद में जमने के कारण बनता है।
- रूबर्ट ड्रॉप्स का नामकरण यूरोप के राजकुमार रूपर्ट के नाम पर किया गया है। इन ड्रॉप्स का कथित तौर पर उत्पादन 17वीं शताब्दी के आरंभ से नीदरलैंड में किया जा रहा है।
- इन ड्रॉप्स में **आंतरिक रूप से बहुत अधिक अवशिष्ट तनाव की विशेषता** पाई जाती है, जो प्रति-सहज गुणों (Counter-intuitive properties) को जन्म देती है। उदाहरण के लिए- जैसे कि बल्बनुमा सिरे पर हथौड़े या गोली के प्रहार को बिना टूटे झेलने की क्षमता, जबकि यदि पिछला सिरा थोड़ा सा भी क्षतिग्रस्त हो तो यह विस्फोटक विघटन का प्रदर्शन करता है।

PIB, AIR, PTI करेंट अफेयर्स वनलाइनर

राष्ट्रीय परिदृश्य

राष्ट्रीय परिदृश्य

- 31 दिसंबर, 2023 को केंद्र सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? **– अरविंद पनगढ़िया**
- राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर, 2023 को पुणे के किस संस्थान को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया? **– सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज (AFMC)**
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से पुणे के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज में टेली-मानस सेल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? **– चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान**
- 1 दिसंबर, 2023 को गांधीनगर में 'ऊर्जा परिवर्तन – सड़क यात्रा और आगे के अवसर' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? **– केन्द्रीय विद्युत एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह**
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 30 नवंबर, 2023 को 10,000वां जन औषधि केंद्र कहां स्थापित किया गया? **– एम्स, देवघर**
- 'बैटल ऑफ माइंड्स'– इंडियन आर्मी क्विज 2023 कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? **– नई दिल्ली**
- 5 दिसंबर, 2023 को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में 'इनो योद्धा 2023' शीर्षक से विचार और नवाचार प्रतियोगिता एवं सेमिनार का आयोजन किसके द्वारा किया गया? **–भारतीय सेना**
- 4 दिसंबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किले में किस मराठा शासक की प्रतिमा का अनावरण किया गया? **छत्रपति शिवाजी महाराज**

विरासत एवं संस्कृति

- यूनेस्को ने गुजरात के किस नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? **– गरबा**
- किस भारतीय मूल की लेखिका को कलात्मक उत्कृष्टता और देश की कला और संस्कृति परिदृश्य को समृद्ध बनाने में उनके योगदान के लिए सिंगापुर के सबसे प्रतिष्ठित कला सम्मान 'कल्चरल मेडलियन' से सम्मानित किया गया? **– मीरा चंद**
- फ्रांस के सेर्गी में किस तमिल कवि और दार्शनिक की प्रतिमा का अनावरण किया गया? **– तिरुवल्लुवर**

आर्थिक परिदृश्य

- विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्द्धात्मकता रैंकिंग (WDCR) 2023 किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? **– इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट (IMD)**
- भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने 26 दिसंबर, 2023 को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में एक शाखा कार्यालय कहां स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? **–गांधीनगर के GIFT सिटी**
- 5 दिसंबर, 2023 को जारी 'ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024' के अनुसार भारत 2030 तक विश्व की किस अर्थव्यवस्था में शामिल होगी? **– विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था**
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 4 दिसंबर, 2023 को कोल्हापुर के इचलकरंजी स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? **– शंकरराव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड**
- बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने साल 2023 के लिए विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में सर्वोच्च रैंकिंग वाली भारतीय महिला का नाम क्या है? **– केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण**
- 11-14 दिसंबर, 2023 के मध्य 'वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी' (WAIPA) के 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया?**– नई दिल्ली**
- एशियाई विकास बैंक (ADB) ने 13 दिसंबर, 2023 को 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान कितने प्रतिशत की है? **– 6.7%**
- बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति 2022-23 नामक रिपोर्ट जारी किसके द्वारा प्रकाशित की गयी? **– भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)**
- 15 दिसंबर, 2023 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ औद्योगिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी? **–इटली**

अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं संगठन

- किस देश को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) परिषद के 2024-25 द्विवार्षिक सत्र के 1 दिसंबर, 2023 को पुनः चुन लिया गया है? **– भारत**
- अर्जेंटीना के नये राष्ट्रपति कौन बने? **– जेवियर माइली**
- विश्व भर के शीर्ष सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी की लिस्ट किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? **– क्वाकरेली साइमंड्स (QS)**
- भारत और अमेरिका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास 'वज्र प्रहार' का 14वां संस्करण 21 नवंबर से 11 दिसंबर, 2023 के मध्य कहां आयोजित किया गया? **– मेघालय के उमरोई छावनी**
- 11 दिसंबर, 2023 को किसे पोलैंड का नया प्रधानमंत्री के रूप चुना गया? **– डोनाल्ड टस्क को**
- 27 दिसंबर, 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? **– न्यूजीलैंड (ऑकलैंड)**
- सुल्तान हैथम बिन तारिक, जो हाल ही में भारत की राजकीय यात्रा पर थे, किस देश के सुल्तान और प्रधानमंत्री हैं? **– ओमान**
- तेल और खनिज संसाधन से समृद्ध क्षेत्र एस्सेक्विबो किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? **– वेनेजुएला और गुयाना**